twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

DD दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | शनिवार, 12 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 236, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

मराठा सैन्य परिदृश्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

नई दिल्ली

मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। शुक्रवार को पेरिस में विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में यह निर्णय लिया गया। यह वैश्विक सम्मान भारत की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत के जश्न का प्रतीक है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की तथा भारतवासियों को इसके लिए बधाई दी।

भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य

मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है, जो 17वीं-19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली एवं रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। महाराष्ट्र के 390 से अधिक किलों में से केवल 12 को इस नामांकन के तहत चुना गया था। मराठा सैन्य परिदृश्य में 12 किले हैं। इसमें सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी किला शामिल है। इनमें से आठ किले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित हैं, जबकि शेष चार महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन हैं।

राजधानी में महसूस किए गए 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके, झज्जर रहा केन्द्र

नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम 7.49 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग घरों से निकल कर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा का झज्जर था। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 थी। इसका केंद्र जमीन से दस किलोमीटर की गहराई पर था। यह 28.68 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 76.72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था। केंद्र झज्जर के नजदीक होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में इसके झटके ज्यादा महसूस किए गए।

'एक देश, एक चुनाव': पूर्व मुख्य जजों ने रखा अपना पक्ष

चुनाव आयोग को एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली को लागू करने में अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए

नई दिल्ली

संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की आज संसद भवन एनेक्सी में एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने आज इसपर कानूनी और संवैधानिक विषयों पर अपना पक्ष रखा। सूत्रों के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति की बंद कमरे में हुई अहम बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक में गंभीर संवैधानिक खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन कई धाराएं अस्पष्ट हैं और इन्हें संसद को स्पष्ट करना होगा। उनके साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने भी ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। दोनों ने बिल की वैधानिकता को सिद्ध किया, लेकिन स्पष्ट भाषा और सुरक्षा उपायों की सिफारिश की। समिति में विभिन्न दलों के 38 सांसद मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक का मसौदा तैयार करना है। इसीलिए हमने ऐसे सम्मानित कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है जो निष्पक्ष रहें और केवल कानून के प्रति प्रतिबद्ध हों। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर रही है। जनता की राय, प्रशासनिक प्रतिक्रिया और संवैधानिक सलाह-सब कुछ ध्यान में रखा जा रहा है। यह प्रक्रिया राजनीति से ऊपर है और हमारी रिपोर्ट राष्ट्रीय हित में तैयार की जाएगी। समिति अपना परामर्श जारी रखे हुए है और आने वाले महीनों में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

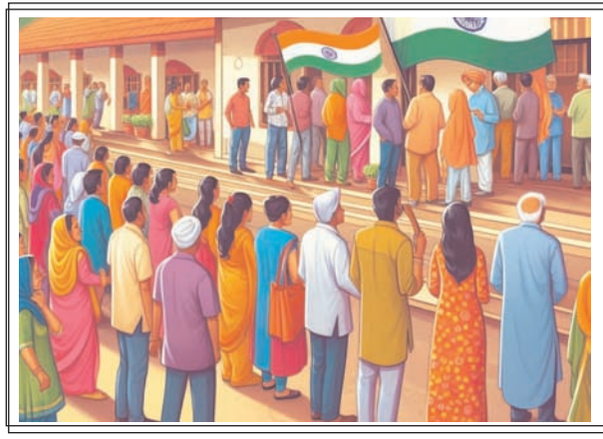

"एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली' राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक

नई दिल्ली

एक देश-एक चुनाव के लिए 129 वें संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की बैठक संसद भवन में हुई। इस मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बैठक के दौरान अपनी बातें भी रखी। दोनों पूर्व सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के चुनाव आयोग को एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली को लागू करने में अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए।

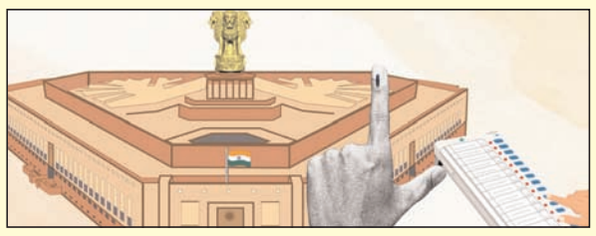

इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी प्रस्तावित संविधान संशोधन कानून में चुनाव निकाय को दी गई "व्यापक शक्तियों" पर सवाल उठाया था। डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने संसदीय समिति को सुझाव दिया कि चुनावों के संचालन पर एक "निगरानी तंत्र" होना चाहिए।

"एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रणाली राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। चौधरी यह भी कहा कि "ये महत्वपूर्ण है कि विधेयक की संवैधानिकता बरकरार रहे ।

'निर्वाचित सरकार का पांच साल का कार्यकाल जरूरी'

न्यायाधीशों में से एक ने यह भी कहा कि निर्वाचित सरकार का पांच साल का कार्यकाल सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसे (पांच साल के कार्यकाल को) किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जाना चाहिए। संविधान (एक सौ उनतीस वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति जांच कर रही है।

बता दें कि देश के दो अन्य पूर्व चीफ जस्टिस यूयू ललित और रंजन गोगोई भी समिति के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। हालांकि दोनों ने एक साथ चुनावों की संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने विधेयक के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए और सुझाव दिए थे। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति, विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्यों में विधानसभाओं और संसद के चुनाव एक साथ कराना है।

विधेयक में संशोधन की जरूरत पड़ी तो करेंगे: पीपी चौधरी

पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के सुझावों पर पीपी चौधरी ने कहा, "जहां तक चुनाव आयोग के प्रावधान का सवाल है, अगर हमें लगता है कि विधेयक में संशोधन की जरूरत है तो हम इसमें संशोधन करेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "हम राष्ट्रीय हित में संशोधन करने के बाद ही संसद को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

सीएम ने दिल्ली हाट आग्निकांड से प्रभावित 24 शिल्पकारों को दी पांच-पांच लाख रुपये की राहत राशि

नई दिल्ली

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आईएनए स्थित बीते 30 अप्रैल को हुए दिल्ली हाट आग्निकांड से प्रभावित 24 शिल्पकारों को पांच-पांच लाख रुपये प्रति स्टॉल की राहत राशि प्रदान की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। यह जानकारी सीएओ दिल्ली ने शुक्रवार को अपने एक्स अकांउट पर साझा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आग ने केवल स्टॉल नहीं बल्कि अनेक कारीगरों के सपनों और वर्षों की तपस्या को भी क्षति पहुंचाई। यह सहयोग केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है कि संकट की घड़ी में दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रभावित शिल्पकारों को दिसंबर 2025 तक निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार उन सभी शिल्पकारों के साथ खड़ी है जो अपनी कला से इस शहर को गरिमा, रंग और पहचान देते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के दावों की एनएसए अजीत डोभाल ने खोली पोल

नई दिल्ली

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बारे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को इस ऑपरेशन के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ककळ मद्रास में अपने संबोधन के दौरान डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। मुझे एक तस्वीर भी दिखा दीजिए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा हो।

स्वदेशी तकनीक पर किया गर्व

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है और हमें गर्व है कि इस ऑपरेशन के दौरान हमने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि हमने सीमापार पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले का फैसला किया था और इसमें सीमावर्ती इलाकों का एक भी ठिकाना नहीं था। हमारे सभी निशाने सटीक रहे और हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि ऑपरेशन 23 मिनट का था और इस दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो प्रति बैरल 130 डॉलर तक पहुंच जाते दाम: हरदीप पुरी

नई दिल्ली

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत की रूस से कच्चे तेल की निरंतर खरीद ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने में मदद की है। रूस से तेल व्यापार रोकने पर कच्चे तेल की कीमतें 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच जातीं।

हमने पूरी दुनिया को महंगाई की मार बचाया- हरदीप पुरी

जब एक प्रेस वार्ता के दौरान रूस के तेल खरीदने के बारे में पूछा गया तो मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया कि रूस प्रतिदिन नौ मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल उत्पादन करता है और यह दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल उत्पादकों में से एक है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी दुनिया को महंगाई की मार बचाया। उन्होंने कहा- "यदि वैश्विक तेल आपूर्ति में से लगभग 97 मिलियन बैरल में से नौ मिलियन बैरल अचानक गायब हो जाते तो पूरी दुनिया को खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की कमी करनी पड़ती, जो असंभव है।"

भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। पुरी ने कहा कि रूस का तेल कभी भी वैश्विक प्रतिबंधों के अधीन नहीं था और भारत ने मूल्य सीमा के तहत छूट पर तेल खरीदकर वैश्विक बाजारों को स्थिरता प्रदान की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ऊर्जा नीति की सराहना की, जिसमें ऊर्जा की उपलब्धता और सस्ती कीमतों को प्राथमिकता दी गई है।

पुरी ने यह भी बताया कि भारत अपने 330 मिलियन घरों को स्वच्छ खाना पकाने की गैस प्रदान कर रहा है।

वोटर सूची पुनरीक्षण: भाजपा ने इंडी गठबंधन को घेरा

नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को लेकर राजद समेत इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। गौरव भाटिया ने कहा कि एसआईआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) वोटिंग में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लाने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए करारा जवाब है। तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानेंगे या नहीं?

राहुल गांधी को बताना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से एक दिन पहले पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? इससे स्पष्ट होता है कि इन नेताओं की सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कोई आस्था नहीं है। न्यायालय के टिप्पणी आने के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की भीतरी कलह पर गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार से कर्नाटक की जनता त्रस्त है।

डॉलर की तुलना में 15 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

नई दिल्ली

ट्रेड टैरिफ की अनिश्चितता और इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों द्वारा जमकर की गई बिकवाली के कारण आज भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरावट का शिकार हो गई। आज रुपया डॉलर की तुलना में 15 पैसे की कमजोरी के साथ 85.79 (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुआ। इसके पहले पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को भारतीय मुद्रा 85.64 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरूआत भी कमजोरी के साथ की थी। इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की कमजोरी के साथ 85.76 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरूआत की थी। दिन के कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए डॉलर की मांग बढ़ने पर रुपया 27 पैसे फिसल कर 85.91 के स्तर तक भी आ गया था, लेकिन इसके बाद डॉलर की आवक बढ़ने पर रुपया सुधर कर 85.78 के स्तर तक पहुंच गया।

हरियाणा में कानून-व्यवस्था पर सीएम सैनी ने की हाई लेवल मीटिंग

प्रदेश में अपराध की स्थिति की करी समीक्षा, दिए सख्त निर्देश

अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून- व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से उच्चाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे प्रत्येक थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में अपराधों में वृद्धि देखी जाए तो त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री वीरवार को देर सायं राज्य में कानून- व्यवस्था पर हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। करीब 4 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों पर पुलिस कार्रवाई, पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधों की रियल टाइम रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए तकनीकी साधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए, ताकि पुलिस तंत्र और अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बन सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने और जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फिरौती मामलों पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, पुलिस अधिकारी मुस्तैदी से करें काम, अपराधियों पर करें सख्त कार्रवाईमुख्यमंत्री ने फिरौती के मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि फिरौती या रंगदारी जैसे गंभीर अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी और सजगता के साथ कार्य करें ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और उनमें यह विश्वास बना रहे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है।

डूब गई राजधानी... पानी में तैर रहे वाहन, गुरुग्राम में कई फीट नीचे धंस गई सड़क

एजेंसी

नई दिल्ली। मानसून की पहली तेज वर्षा ने सड़कों पर जलभराव रोकने के इंतजामों की पोल खोल दी। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर-70 स्थित एसपीआर रोड कई फीट नीचे धंस गई। सड़क धंसने से एक ट्रक भी गिर गया। बताया गया कि इस ट्रक में बीयर भरी हुई है। वहीं, कई जगहों पर जलभराव व जाम की स्थिति होने से गुरुवार सुबह भी लोगों को ऑफिस पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि शुरू हुई वर्षा देर रात तक जारी रही। कई सड़कों पर जलभराव हुआ और एनसीआर में महाजाम की स्थिति बन गई। दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में लोग कई किलोमीटर के लंबे जाम में घंटों फंसे रहे। वाहनों के बीच रास्ते में बंद होने से कई लोगों पर दोहरी मार पड़ी। हालत ऐसी थी कि शाम को कार्यालयों से निकले कई लोग मध्यरात्रि के बाद घर पहुंचे। दिल्ली में 150 से अधिक स्थानों पर जलभराव और 200 से अधिक स्थानों पर जाम लगा। वहीं, सरिता विहार अंडरपास में जलभराव के बीच जगुआर और जखीरा में एक अन्य कार फंस गई। जलभराव से गुजरने में कई बसें जहां-तहां फंस गईं और इन बसों में बैठीं सवारियों

को वैकल्पिक व्यवस्था कर अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। कुल मिलाकर सड़कों पर जगह-जगह जलभराव ने दिल्ली सरकार के मानसून को लेकर तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। बताया गया कि देर रात दो बजे तक कहीं से कोई जनहानि की सूचना नहीं थी।

दो घंटे एक ही स्थान पर खड़ी रहीं एंबुलेंस

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर खेड़कीदौला से लेकर रजोकरी बार्डर तक 24 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया और घंटों तक वाहनों के पहिये थम गए। बताया गया कि जाम ऐसा था कि सैकड़ों वाहनों के साथ कई एंबुलेंस भी एक से दो घंटे तक एक ही स्थान पर खड़े रहे। बढ़ते-बढ़ते जाम दिल्ली तक पहुंच गया। गाजियाबाद का भी बुरा हाल रहा। राजनगर एक्सटेंशन में लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर भी काफी संख्या में वाहनों की कतारें लगी रहीं।

मिंटो ब्रिज अंडरपास में नहीं भरा पानी : हर बार वर्षा में मिंटो ब्रिज अंडरपास में जलभराव होता था, लेकिन इस बार वहां पानी की निकासी की व्यवस्था होने के कारण लोगों को राहत मिली। कई लोगों ने यहां से फेसबुक लाइव भी किया।

गंभीरा ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या 15 तक पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी

एजेंसी

वडोदरा। आणंद और वडोदरा शहर को जोड़ने वाले गंभीरा पुल हादसे में मरने वाले की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। प्रशासन का कहना है कि अभी भी तीन लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नदी में दो और वाहनों के फंसे होने की आशंका है। एक दिन पहले बुधवार

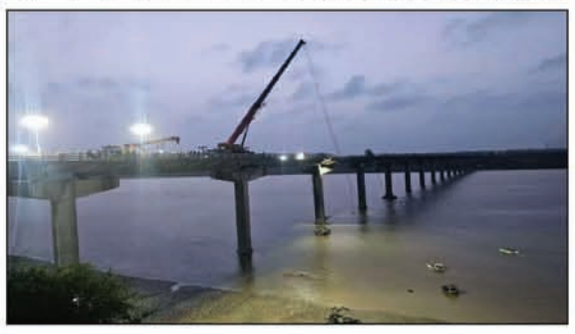

सुबह यह हादसा हुआ था। कलेक्टर के मुताबिक हादसे की चपेट में आने वाले दो अन्य वाहन जो नदी में गिरने के करीब थे, उन्हें सुरक्षित खींच लिया गया है। वडोदरा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक रोहन आनंद ने बताया कि पुल का 10 से 15 मीटर लंबा स्लैब सुबह भरभरा कर गिर गया। उधर, राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि राज्य सरकार ने इस नदी पर नया पुल बनाने की त्वरित मंजूरी दे दी है। इसके लिए 212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। गंभीरा ब्रिज 900 मीटर लंबा है, जिसका उद्घाटन साल 1985 में हुआ था। तीन साल पहले प्रशासन द्वारा इसकी जांच कराई गई थी और उस समय रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बावजूद पुल आवागमन के लिए चालू रखा गया था। बताया जाता है कि नौ दिन पहले भी इसका निरीक्षण किया गया था। वह तो गनीमत रही कि नदी में पानी कम था, अन्यथा हादसे में और लोगों की भी जान जा सकती थी।

हरियाणा के पांच जिलों में भूकंप के झटके

चंडीगढ़। हरियाणा के पांच जिलों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के दौरान भूकंप के झटकों से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार सहित कई हिस्सों में गुरुवार

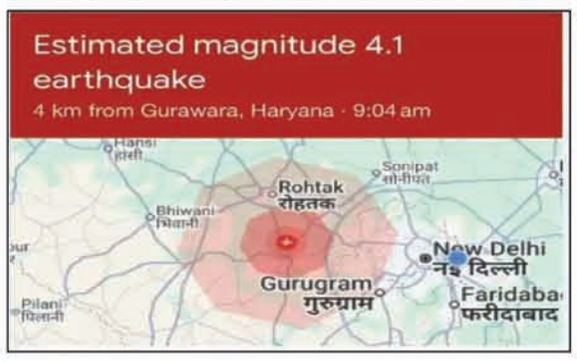

सुबह करीब नौ बजकर पांच मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए। इसका केंद्र झज्जर रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई। यहां करीब 10 कि.मी. नीचे धरती में हलचल महसूस की गई है। किसी ने जमीन के नीचे ट्रेन की तरह आवाज सुनाई देने का दावा किया तो किसी ने डरावनी आवाज सुनने की बात कही। सोनीपत निवासी अजयदीप के अनुसार इस तरह के झटके पहले कभी महसूस नहीं किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ज्यादातर लोग अपने दफ्तरों व दैनिक कामकाज शुरू करने की तैयारी में थे। गुरुग्राम निवासी नर्सिंग ऑफिसर पूनम सहरावत ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक रहे, लेकिन उसका अहसास हुआ है। कई लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भूकंप के बाद से जिलों में रिपोर्ट ली जा रही है। अभी कहीं से भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट निमिषा की फांसी पर रोक की याचिका पर 14 जुलाई को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय हत्या के एक मामले में केरल निवासी नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को निर्धारित फांसी की सजा पर रोक और उसकी रिहाई के लिए केंद्र सरकार को कूटनीतिक प्रयास करने का निर्देश देने की मांग संबंधी एक याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने 'सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल' नामक एक संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रागेंथ बसंत के शीघ्र सुनवाई के अनुरोध के बाद संबंधित याचिका को (14 जुलाई के लिए) सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता बसंत ने 'विशेष उल्लेख' के दौरान अदालत से यह अनुरोध किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि शरीयत कानून के अनुसार, अगर पीड़ितों के रिश्तेदार 'खूंबहा' स्वीकार करने को तैयार हों, तो किसी व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है। खूंबहा का मतलब है कि पीड़ित परिवार को मुआवजे का प्रस्ताव दिया जाये और वे इसे लेने को तैयार हों तो अभियुक्त की सजा माफ की जा सकती है। कई अरब मुल्कों में ऐसा कानून लागू है। उन्होंने आग्रह करते हुए अदालत के समक्ष कहा, कृपया आज या कल सूचीबद्ध करें, क्योंकि 16 जुलाई फांसी की तारीख है। राजनयिक माध्यम से बातचीत के लिए भी समय की आवश्यकता होती है। याचिका में फांसी पर रोक और रिहाई के लिए भारत सरकार से कूटनीतिक बातचीत के जरिए प्रयास करने की गुहार लगायी गयी है। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति धूलिया ने अधिवक्ता से पूछा कि उस व्यक्ति को मौत की सजा क्यों सुनाई गयी। इस पर श्री बसंत ने जवाब दिया, निमिषा (नर्स) केरल की रहने वाली एक भारतीय नागरिक है। वह वहाँ नर्स की नौकरी के लिए गयी थी।

बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

सुधार गलत नहीं लेकिन टाइमिंग पर सवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्वाचन आयोग की इस पहल को गलत नहीं ठहराया, लेकिन इसके समय पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि ÷मतदाता सूची से गैर-नागरिकों को हटाने का प्रयास उचित है, लेकिन यह प्रक्रिया अगर चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू की जाती है, तो उसकी मंशा और प्रभाव पर सवाल उठना स्वाभाविक है।÷ जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसकी टाइमिंग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डाल सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। प्रमुख याचिकाकर्ताओं में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ-साथ

कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। इनमें आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव गुट) के अरविंद सावंत और झामुमो व माले के नेता भी शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण अभियान को चुनाव से पहले एक 'राजनीतिक कदम' बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत 7.9 करोड़ से अधिक नागरिकों की पात्रता पर सवाल उठेंगे और मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड जैसी पहचान भी पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं राकेश द्विवेदी, केके वेणुगोपाल और मनिंदर सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग का उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आयोग को राहत तो दी है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता के मद्देनज़र इस प्रक्रिया की टाइमिंग का गंभीरता से मूल्यांकन होना आवश्यक है। मामले की अगली सुनवाई जल्द तय की जाएगी।

अमरनाथ यात्रा: 7,307 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू से रवाना

एजेंसी

जम्मू। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 7,307 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार तीर्थयात्री आज सुबह 284 वाहनों में जम्मू के आधार शिविर से रवाना हुए। इस जत्थे में 5534 पुरुष, 1586 महिलाएं, 25 बच्चे, 138 साधु और 24 साध्वियां शामिल थीं। इनमें से 3081 तीर्थयात्री तड़के 3:15 बजे बालटाल आधार शिविर और 4226 तीर्थयात्री तड़के 3:58 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से वे पवित्र गुफा की अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना होंगे।वहीं लगभग 17,000 तीर्थयात्रियों ने दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित श्री अमरनाथ मंदिर में हिमलिंग के दर्शन किए जिससे इस वर्ष पहले सप्ताह में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 1,28000 हो गई है।

फडणवीस ने 'सिंदूर ब्रिज' का किया उद्घाटन, बोले- 'गुलामी की निशानी को हटा रहे हैं'

एजेंसी

मुंबई । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 'सिंदूर ब्रिज' का उद्घाटन किया। यह ब्रिज पहले कार्नैक ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी मौजूद थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 'सिंदूर ब्रिज' के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, 'आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में 'सिंदूर ब्रिज' का उद्घाटन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि पुराना कार्नैक ब्रिज बहुत जर्जर हालत में था, इसलिए उसे तोड़ दिया गया था और उसकी जगह एक नया ब्रिज बनाया गया है।' उन्होंने कहा, 'कार्नैक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया था, खासकर सतारा के प्रताप सिंह राजे और नागपुर के उद्धव राजे को अलग-अलग षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया, इसलिए हमने अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर सिंदूर का नाम देने का निर्णय लिया।

हम सभी जानते हैं कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारतवासियों के मन में बसा हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पहली बार अपनी ताकत को दिखाया और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को खत्म करने का काम किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री के बयान का जिक्र करते हुए कहा, 'पीएम मोदी ने बार-बार यह कहा है कि स्वतंत्रता के अमृतकाल में गुलामियों की निशानी को मिटाकर हमें अपनी निशानियों को तरजीह देनी है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये निर्णय लिया गया है।बता दें कि यह पुल दक्षिण मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम बंबई प्रांत के पूर्व गवर्नर जेम्स रिवेट कार्नैक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1839 से 1841 तक इस पद पर कार्य किया था। अब इस पुल का नाम बदलकर (ऑपरेशन सिंदूर पर) 'सिंदूर ब्रिज'कर दिया गया है।

उपराष्ट्रपति ने भारत की बौद्धिक विरासत को वैश्विक संदर्भ में सराहा

एजेंसी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में आयोजित भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) पर प्रथम वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि और वैश्विक महत्व को रेखांकित करते हुए देश की बौद्धिक विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। सम्मेलन में भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपराओं को समकालीन शोध और शिक्षा प्रणाली से जोड़ने पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के उद्धरण के माध्यम से भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को रेखांकित किया। उन्होंने इसे शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति बताया। धनखड़ ने कहा कि लंबे समय तक पश्चिमी सिद्धांतों को सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि भारत की स्वदेशी ज्ञान परंपराओं को नकारात्मक दृष्टि से देखा गया। आज़ादी के बाद भी यह मानसिकता कुछ हद तक जारी रही। उन्होंने कहा कि भारत केवल 20वीं सदी के मध्य में बनी राजनीतिक संरचना नहीं है

बल्कि सभ्यतागत सातत्य है, जो चेतना, अन्वेषण और ज्ञान की एक बहती नदी के रूप में आज भी विद्यमान है। उपराष्ट्रपति ने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और ओदंतपुरी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये न केवल शिक्षा के केंद्र थे बल्कि वैश्विक ज्ञान समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्ञान केवल पांडुलिपियों में नहीं, बल्कि समुदायों की परंपराओं, प्रथाओं और पीढ़ियों के अनुभवों में भी समाहित होता है। उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में लिखित शब्द और जीवंत अनुभव दोनों को समान महत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया। धनखड़ ने कहा कि अतीत का ज्ञान नवाचार में बाधा नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संवाद संभव है।

स्वच्छ भारत मिशन ने बदली आगरा की तस्वीर, 6 साल में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन कचरा प्रबंधन

आगरा/नई दिल्ली। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन न सिर्फ देश को साफ-सुथरा, हरा-भरा बना रहा है बल्कि देशवासियों को गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी योगदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से इस मिशन की मदद से 1.9 मिलियन मीट्रिक टन कचरे को हटाकर फिर से हरा-भरा कर दिया गया। यह जानकारी आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से दी गई। छह साल पहले तक आगरा के कुबेरपुर इलाके में हर रोज हजारों टन कचरा फेंका जाता था। ये जगह एक जहरीली डंपिंग साइट बन चुकी थी। इस इलाके में 1.9 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा ठोस कचरा जमा था।

साल 2007 से लेकर 2019 तक यह इलाका शहर के लिए गंदगी और बीमारी का केंद्र बना रहा। लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और उत्तर प्रदेश सरकार के सफाई अभियान ने इस इलाके को फिर से हरा-भरा कर दिया। बायोरेमेडिएशन और बायोमाइनिंग तकनीकों की मदद से दिसंबर 2024 तक सरकार ने करीब 230 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि खर्च कर उस इलाके से करीब 1.9 मिलियन मीट्रिक टन कचरा हटा हटाया। इस इलाके से कचरा हटने के बाद जो 47 एकड़ जमीन खाली हुई, उसे फिर से साफ-सुथरा बनाया गया। इसमें से 10 एकड़ में मियावाकी पद्धति से शहरी जंगल तैयार किया गया, 5 एकड़ में आधुनिक सैनिटरी लैंडफिल बनाया गया और बाकी जमीन को ग्रीन ज़ोन में बदला गया। इसके अलावा रोजाना होने वाले नए कचरे को स्मार्ट तरीके से संभालने की व्यवस्था भी की गई। साल 2019 में एक 300 टन प्रतिदिन (टीडीपी) क्षमता का वेस्ट-टू-कंपोस्ट प्लांट लगाया गया।

पांच देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच देशों की आठ दिन की यात्रा संपन्न होने के बाद गुरुवार सुबह स्वदेश लौट आए।प्रधानमंत्री दो जुलाई को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रवाना हुए थे। यात्रा के अंतिम चरण में वह नामीबिया पहुंचे थे जहां उन्होंने नामीबियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। श्री मोदी ने नामीबिया की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। इससे पहले ब्राजील में उन्होंने 17 वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया और सदस्य देशों के सामने विभिन्न विषयों पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया।

राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे संविधान की रक्षा : गिरिराज सिंह

एजेंसी

बेगूसराय । केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को डमी बताया और कहा कि संविधान की सही मायनों में रक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान की किताब दिखाए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी खुद एक डमी हैं। उनके पास संविधान की एक डमी किताब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी इसकी (संविधान) रक्षा करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य ऐसे डमी लोगों से छुटकारा दिलाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर चढ़ने से रोके जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता।

अब तक सामाजिक मान्यता यही थी कि ये लोग राज्य के बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी ने इन दोनों (कन्हैया और पप्पू यादव) का अपमान किया है। बता दें

कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महागठबंधन की ओर से आयोजित विरोध मार्च में शिरकत की। हालांकि, 'बिहार बंद' के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया था। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, हमें वाहन पर चढ़ने नहीं दिया गया, अंदर सभी लोग कांग्रेस से थे। यह मेरी जिंदगी की लड़ाई है, मेरे समाज की लड़ाई है। यह संविधान की रक्षा और अल्पसंख्यकों के दर्जे की लड़ाई है। इसमें सम्मान और अपमान की क्या बात है? कहीं कोई अपमान की बात नहीं है, हम लोगों का संबंध सीधे मतदाताओं से है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने देश के दो राज्यों में हुईं दुखद घटनाओं पर चिंता व्यक्त की

एजेंसी

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने राजस्थान के चुरू जिले में भारतीय वायु सेना के जगुआर लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले में एक पुल का ढहने की घटनाओं को दुखद बताया है। उपाध्यक्ष प्रो. सलीम इंजीनियर ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करके घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में पुल ढह जाने की वजह से कई वाहन नदी में गिर गए, जिसमें कम से कम दस लोगों की जान चली गई। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों और समुदायों के साथ एकजुटता व्यक्त करके ज़मीनी स्तर पर आपातकालीन टीमों और स्थानीय अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही ये त्रासदियां बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों के मानकों पर गंभीर प्रश्न उठाती हैं। उन्होंने सरकार से विमान दुर्घटना और पुल के ढहने की घटना की पारदर्शी और गहन जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए।

भाजपा ने बिहार बंद को बताया विपक्ष की साजिश का हिस्सा

पटना। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार बंद को नियोजित साजिश बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये लोग या तो अदालत पर भरोसा करें या फिर सड़कों पर प्रदर्शन करें। जब सुप्रीम कोर्ट में कल (गुरुवार को) ही सुनवाई होनी है, तो आज सड़क पर उतरकर क्या किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गयी है। क्या ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में ऐसे लोग बने रहें, जिन्हें उसमें होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि घुसपैठिए। रविशंकर प्रसाद ने पटना में पत्रकार वार्ता में कहा कि सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि देश में सांसद या विधायक कौन बनेगा? इसका फैसला वोटर करते हैं। वोट वही डाल सकता है, जो भारत का नागरिक होगा और उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होगी। जो सामान्य रूप से उस स्थान का निवासी हो, जहां से वह वोट डालता है। इसलिए वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, तो इसमें विपक्षी दलों को किस बात की परेशानी है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई नहीं है कि कई बार रोहिंग्या या अन्य लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लेते हैं? जब पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है ।

सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते रंगेहाथों किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया। सीबीआई की तरफ से एक्स पोस्ट में बताया गया है कि दिल्ली के द्वारका उत्तर थाने में तैनात एएसआई और एक हेड कांस्टेबल ने पहले 5 हजार रुपये की एडवांस रिश्वत की मांग की और उसके बाद हर महीने 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक देने को कहा। बातचीत के बाद मामला 10 हजार रुपये एकमुश्त और हर महीने 2 हजार रुपये प्रति व्यक्ति पर तय किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता से कुल 35 हजार रुपये एडवांस में ले लिए गए। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और 8 जुलाई को दोनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर आरोपित एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार एएसआई से पूछताछ जारी है, जबकि उसके साथी हेड कांस्टेबल की भूमिका की भी जांच चल रही है। फिलहाल सीबीआई पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी है और जल्द ही इस घूसकांड से जुड़े बाकी पहलुओं का खुलासा हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने वडोदरा में पुल ढहने की घटना पर जताया दुख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा जिले में पुल ढहने की घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बुधवार को शोक संदेश साझा किया गया। संदेश में लिखा गया, वडोदरा जिले में पुल ढहने से हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, हादसे में घायल हुए व्यक्तियों को 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि गुजरात में एक पुराने ब्रिज के टूट जाने से वहां से गुजर रहे दो ट्रक, एक बोलेरो समेत चार वाहन महिसागर नदी में समा गए।

ऊर्जा शिक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत : धर्मेंद्र प्रधान

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा शिक्षा को लेकर दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, बावजूद इसके देश की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी भी वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है। प्रधान भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में 'भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा शिक्षा = अवसर और चुनौतियां' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में देश के शीर्ष 100 एनआईआरएफ रैंकिंग वाले संस्थानों और ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित अन्य संस्थानों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत को 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसे में एक ऐसी स्मार्ट रणनीति की आवश्यकता है जो शैक्षणिक ज्ञान को सामाजिक कल्याण से जोड़ सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल ऊर्जा शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की दिशा में एक लंबी

यात्रा की आधारशिला बनेगी। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से आग्रह किया कि वह स्कूल स्तर के छात्रों के लिए भी ऊर्जा शिक्षा का एक समर्पित पाठ्यक्रम विकसित करने में सहयोग करे। धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए सराहना की और कहा कि यह प्रयास भविष्य के लिए ऊर्जा क्षेत्र में योग्य मानव संसाधन तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा, जलवायु और सतत विकास जैसे विषय अब केवल वैज्ञानिक विमर्श तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि इन्हें शिक्षा के हर स्तर पर समावेशित करना समय की मांग है। इस अवसर पर उन्होंने %ऊर्जा संगम% पोर्टल का शुभारंभ भी किया, जो देशभर के शोध, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रयासों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 'ऊर्जा संगम' (https://oorjasangam.iitd.ac.in/) नामक एक वेबसाइट लॉन्च की, जो देश में ऊर्जा, जलवायु और सतत विकास से संबंधित अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एक 'सिंगल स्टॉप पोर्टल' के रूप में काम करेगी। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंजन बनर्जी ने बताया कि कार्यशाला में एनआईआरएफ के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम विकास, उद्योग साझेदारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण पर चर्चा की गई। ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अशु वर्मा ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य भावी पीढ़ी को सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तैयार करना है।

उदयपुर फाइल्स पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी की मौलाना अरशद मदनी ने सराहना की

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में 'उदयपुर फाइल्स' नामक फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने सख्त टिप्पणी की है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुख्य न्यायाधीश कीटिप्पणी की सराहना की है।सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संविधान जो निर्देश देता है, उसका पालन होना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ कतई नहीं है कि किसी धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने सेंसर बोर्ड और फिल्म निर्माता के वकीलों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के वकीलों के सामने पूरी फिल्म की स्क्रीनिंग की जाए। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी की सराहना करते हुए आज की न्यायिक कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अदालत फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद इसके रिलीज़ के संबंध में

मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए संविधान की रोशनी में ऐसा फैसला देगी जिससे संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होगी। यह फिल्म उदयपुर में हुई एक हत्या की घटना को आधार बनाकर बनाई गई है।

बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के सर्वोत्तम तरीकों पर दो दिवसीय कार्यशाला

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) 'भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का इस्तेमाल करके बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के सर्वोत्तम तरीकों' पर गुरुवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। यह दो दिवसीय ऑफलाइन कार्यशाला 10-11 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल इसका उद्घाटन करेंगे। यह बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल पर आधारित पहला सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम है, और यह बधिर शिक्षा के लिए शैक्षणिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बताया कि इस पहल का

उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) पाठ्यक्रम के बधिर छात्रों और पढ़ने-लिखने में चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य बधिर व्यक्तियों के बीच अंग्रेजी साक्षरता में सुधार के लिए प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोणों की पहचान करना है। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि डीटीआईएसएल पाठ्यक्रम के बेसिक इंग्लिश भाग 1 और 2 मॉड्यूल के भविष्य के संशोधन में योगदान देगी। कार्यशाला में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति भाग लेंगे जिनमें हैप्पी हैंड्स स्कूल फॉर द डेफ के संस्थापक एवं निदेशक, बधिर छात्रों के लिए अंग्रेजी साक्षरता पर शोधकर्ता डॉ. सिबाजी पांडा वरिष्ठ सलाहकार, बधिरों के लिए द्विभाषी शिक्षा के विशेषज्ञ, 20 से अधिक वर्षों का अनुभव वाले सुनील सहस्त्रबुद्धे शामिल है।

कृषि मंत्रालय ने सात नए उत्पादों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की दी स्वीकृति

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के साथ ही कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सात नए उत्पादों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका मकसद कृषि उत्पादों का कवरेज बढ़ाना और किसानों और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के अधिक अवसर प्रदान करना है। इन सात उत्पादों में गन्ना, मर्चा चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और बनारसी पान शामिल हैं। इन सात उत्पादों सहित ई-नाम प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की संख्या बढ़कर अब 238 हो गई हैं। कृषि मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने 7 अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। ये नए उत्पाद मापदंड राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय-विशेषज्ञों और एसएफएसी सहित

प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाती है और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देती है। व्यापार योग्य मापदंडों का निर्माण प्रत्येक उत्पाद के लिए श्रेणी या रेंज प्रदान करता है और उपज की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।

ये नए स्वीकृत व्यापार योग्य मापदंड ई-नाम पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता और सुदृढ़ होगी। इस कदम से किसानों को बेहतर बाज़ार पहुंच, बेहतर मूल्य निर्धारण और बेहतर गुणवत्ता का आश्वासन मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोध और फीडबैक के आधार पर, मौजूदा 4 उत्पादों के व्यापार योग्य मापदंडों में संशोधन किया गया है, ये हैं-सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न व ड्रैगन फ्रूट।

इस साल वायु सेना के पांच विमान क्रैश हुए, सिर्फ 4 महीने में 3 जगुआर दुर्घटनाग्रस्त

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्थान के चूरू में दुर्घटनाग्रस्त हुए जगुआर फाइटर प्लेन को मिलाकर इस साल अब तक वायु सेना के पांच विमान क्रैश हो चुके हैं। सिर्फ 4 महीने में 3 जगुआर जेट क्रैश हुए हैं। ये घटनाएं पुराने जगुआर बेड़े और इसकी परिचालन सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। माना जा रहा है कि चूरू में क्रैश हुआ विमान डेरिन-III अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसके अलावा लड़ाकू विमान मिराज और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एएन-32 भी इसी साल दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस साल वायु सेना के फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने की पहली घटना मध्यप्रदेश के शिवपुरी के पास हुई थी। ग्वालियर एयर बेस से 6 फरवरी को रूटीन फ्लाइंग के लिए उड़ान भरने वाला मिराज-2000 दुर्घटना का शिकार हो गया था। यह एयरक्राट मिराज का ट्रेनर वर्जन था। इस घटना में दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट हो गए थे। इसी साल 7 मार्च को वायु सेना के 2 विमान हादसे हुए। एक घटना हरियाणा में हुई तो दूसरी पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में हुई। हरियाणा में तकनीकी खराबी के बाद जगुआर को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। इस एयरक्राफ्ट ने अंबाला एयर बेस से उड़ान भरी थी। उड़ान के कुछ देर बाद ही फाइटर प्लेन पंचकूला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर क्रैश कराया, जिससे किसी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई। इसी दिन पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में भारतीय वायु सेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एएन-32 आपात लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चालक दल के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए। रूस निर्मित मध्यम लिफ्ट सामरिक विमान एंटोनोव-32 (एएन-32) को 80 के दशक के प्रारंभ में शामिल किया गया था और लगभग 100 विमान वायु सेना में सेवारत हैं।? इस साल का चौथा विमान हादसा 2 अप्रैल को हुआ, जब गुजरात के जामनगर में ट्विन सीटर फाइटर जेट जगुआर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। जामनगर एयरफील्ड से दो सीटर जगुआर विमान रात में 10.20 बजे रात्रि मिशन के लिए उड़ान भर रहा था। इसी दौरान पायलटों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को आबादी क्षेत्र से बाहर निकालने की पहल की, ताकि एयरफील्ड और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस दौरान पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे पायलट को जामनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायु सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।

भगवान वाल्मीकि समूचे समाज के पथप्रदर्शक हैं : चुघ

एजेंसी

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ दिल्ली के पंचकुइयां रोड स्थित प्राचीन वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महंत पीठाधीश्वर स्वामी कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज गुरु पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर तरुण चुघ ने कहा कि भगवान वाल्मीकि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा हैं। उनका जीवन, उनका विचार और उनका मार्गदर्शन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प का आधार है। स्वामी कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज ने भी वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए बीते 11 वर्षों में हुए ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने विशेषकर दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लिए किये गए प्रयासों को उल्लेखनीय बताया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी प्रकाश तंवर भी उपस्थित रहे।

सीएम रेखा गुप्ता ने 'जनसेवा सदन' में सुनी जनता की बात

अधिकारियों को दिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार सिविल लाइंस स्थित 'मुख्यमंत्री जनसेवा सदन' में जनता से सीधी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। अब तक वह शालीमार बाग स्थित अपने निवास पर ही जनसुनवाई कर रही थीं, लेकिन अब उन्हें एक स्थायी और व्यवस्थित जगह मिल गई है जहां वे लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों का हल निकाल रही हैं। जनसेवा सदन में सुबह 8 से 10 बजे तक चली जनसुनवाई में जल बोर्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और नगर निगम सहित करीब एक दर्जन विभागों के अफसर मौजूद थे। लोगों ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, दाखिला, अतिक्रमण और अपराध से जुड़ी अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय के भीतर समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई

उनके लिए सिर्फ एक सरकारी काम नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद है। उन्होंने लोगों की आंखों में उम्मीद और दिलों में भरोसा देखा कि सरकार उनकी बात सुन रही है और हल निकालने में लगी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुनवाई नहीं, समाधान की सोच के साथ काम कर रही है और हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। जनसेवा सदन में बैठने, पीने के पानी और आसान प्रवेश जैसी सुविधाएं भी दी गई थीं, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है और दिल्ली को एक संवेदनशील, सशक्त और न्यायप्रिय शहर बनाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है।

आईपीयू के मेडिकल एवं नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिले के लिए 11 जुलाई से शुरू होगा पंजीकरण

नई दिल्ली। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपीयू) में मेडिकल एवं नर्सिंग प्रोग्रामों में दाखिले के लिए 11 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए 21 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। वे उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही 2500 रुपये आवेदन शुल्क जमा कर पंजीकरण कर लिया है, वे अपने फॉर्म में रीजन, कैटेगरी और रैंक आदि से संबंधित जानकारी में संशोधन कर सकते हैं। इसके साथ ही नीट यूजी का रैंक कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि भी फॉर्म के साथ 21 जुलाई तक अपलोड किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को तैयार रखें और आवेदन प्रक्रिया को अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लें। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइटों www.ipu.ac.in और www.ipu.admissions.nic.in पर उपलब्ध है।

दिल्ली में चोरों पर पुलिस का शिकंजा, तुलसी और अरुण की गिरफ्तारी से 22 मामले सुलझे

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ पुलिस टीम ने दो कुख्यात चोरों तुलसी और अरुण को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद की गई, जो रोहिणी के अमन विहार थाने से चुराई गई थी। पुलिस का दावा है कि तुलसी और अरुण की गिरफ्तारी के बाद चोरी के 22 मामलों को सुलझा लिया गया है। दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोग चोरी के मोबाइल फोन बेचने के इरादे से मिंटो रोड टर्मिनल, शिवाजी पार्क के पास चोरी की स्कूटी पर आने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर एसीपी ऑपरेशन्स सुरेश खुंगा की देखरेख में इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

इस टीम में सब-इंस्पेक्टर ओमवीर त्यागी, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर प्रताप सिंह, यजुरवेंद्र, हेड कांस्टेबल मुनेश, धीरज, विकास, और कांस्टेबल लोकेंद्र, सूरजपाल और अनिल शामिल थे। पुलिस ने शिवाजी पार्क के पास जाल बिछाया और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

पकड़े गए व्यक्तियों ने अपनी पहचान तुलसी (41 वर्ष, मोतिया खान, पहाड़गंज) और अरुण (33 वर्ष, बस्ती लाल सिंह, किशन गंज, करोल बाग) के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उनके पास से दो चोरी के मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद हुई, जो अमन विहार थाने में दर्ज चोरी के मामले से संबंधित थी। पूछताछ में तुलसी ने खुलासा किया कि वह पिछले 3-4 महीनों में अपने साथियों अरुण, बिरजू और नरेश के साथ दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मोबाइल, बैग और वाहन चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है। तुलसी पहले भी दिल्ली के लाहौरी गेट, हौज काजी, सदर बाजार और कमला मार्केट थानों में चोरी के 10 से अधिक मामलों में लिप्त रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जामा मस्जिद, डीबीजी रोड, करोल बाग और अन्य थानों में दर्ज 22 चोरी के मामले सुलझ गए।

खानपुर में अकेले रह रहे व्यक्ति ने की खुदकुशी

नई दिल्ली। दक्षिणी जिले के नेब सराय थाना क्षेत्र के खानपुर इलाके में एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामले की सूचना मिलते पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। जांच में मृतक की पहचान आर. चंद्र शेखर के रूप में हुई। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। शव सड़ी गली अवस्था में था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दक्षिणी जिल के डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार शेखर अकेले तुगलकाबाद एक्सटेंशन में पिछले दो वर्षों से किराए के कमरे में रह रहा था।

लड़कियों को गुमराह करने वाला दिल्ली पुलिस का फर्जी अफसर गिरफ्तार

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) पुलिस ने खुद को दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताने वाले 23 वर्षीय साहिल कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपित फर्जी पहचान पत्र और वर्दी का इस्तेमाल कर महिलाओं को गुमराह कर रहा था और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर सोशल सर्कल में धौंस जमाता था। पुलिस के मुताबिक सात जुलाई की दोपहर करीब 3:30 बजे टर्मिनल-3 पर सीआईएसएफ की सतर्कता टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, जो दिल्ली पुलिस की टी-शर्ट पहने हुए था और खुद को सब-इंस्पेक्टर बता रहा था। पूछताछ के दौरान वह अपनी पोस्टिंग और पहचान को लेकर सही जानकारी नहीं दे सका। उसकी तलाशी में एक फर्जी पुलिस पहचान पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र,

दिल्ली पुलिस अकादमी की स्टैम्प लगी डायरी और पुलिस वर्दी में खींची गई तस्वीरें मिलीं। सीआईएसएफ की शिकायत पर आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपित साहिल ने बताया कि वह कक्षा 12 तक पढ़ा है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वह रोहिणी में अपने रिश्तेदार के साथ रह रहा था। साहिल ने कबूल किया कि उसने दिल्ली कैंट क्षेत्र से पुलिस की वर्दी खरीदी थी और फोटोशॉप के जरिए फर्जी पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र तैयार किया था। साहिल ने यह भी स्वीकार किया कि वह कई महिलाओं को यह कहकर गुमराह कर चुका है कि वह दिल्ली पुलिस में वर्ष 2024 बैच का सब-इंस्पेक्टर है और आईजआई एयरपोर्ट पर तैनात है। उसने सोशल मीडिया के जरिए एक महिला पुलिस कर्मचारी से भी संपर्क किया था, जिसने बाद में उसकी सच्चाई की पुष्टि की। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साहिल ने इस फर्जी पहचान का और कहां-कहां दुरुपयोग किया है।

संपादक की कलम से

भारत को एक राष्ट्र के रूप में जल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी

डे जीरो–एक ऐसा शब्द है जो अब केवल एक संभावित आपदा नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक का प्रतीक बन चुका है। यह शब्द पहली बार 2018 में वैश्विक स्तर पर चर्चा में तब आया जब दक्षिण अफ्रीका का कैपटाउन शहर पानी की आपूर्ति पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। डे जीरो वह दिन होता है जब शहर के सभी नल बंद कर दिए जाते हैं, और नागरिकों को सार्वजनिक वितरण केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़े होकर सीमित मात्रा में पानी प्राप्त करना पड़ता है। कैपटाउन में यह सीमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर निर्धारित की गई थी। हालांकि इस संकट का कारण केवल जलवायु परिवर्तन या वर्षा की अनिश्चितता नहीं था–यह दशकों की नीति विफलता, शहरों का अति-विस्तार, परंपरागत जल स्रोतों की उपेक्षा और जल प्रबंधन में बड़ी खामियों का संयुक्त परिणाम था।

कैपटाउन ने कड़ी नीतियों और नागरिक सहभागिता से इस आपदा को कुछ समय के लिए टाल दिया है। लेकिन पानी की गंभीर किल्लत की आहट अब भारत के दरवाजे तक होने लगी है। भारत जैसे देशों में, जहां जनसंख्या अत्यधिक है, शहरीकरण अनियंत्रित है, और भूजल दोहन पर कोई स्पष्ट नियंत्रण नहीं–डे जीरो अब भविष्य की आशंका नहीं, बल्कि एक आसन्न यथार्थ है।

बेंगलुरु, जिसे कभी झीलों का शहर कहा जाता था, आज जल संकट के सबसे भीषण दौर से गुजर रहा है। यहां की अधिकांश झीलें अब या तो कचरा डंपिंग साइट बन चुकी हैं या अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गईं। भूजल स्तर हर वर्ष 10-12 मीटर की दर से नीचे जा रहा है। बेंगलुरु में डे जीरो की आंशिक झलक तब देखने को मिली जब पूरे शहर में टैंकर के पानी पर निर्भरता बढ़ी।

चेन्नई भी 2019 में डे जीरो जैसे संकट का सामना कर चुका है जब उसके चारों जलाशय सूख गए थे। वहीं दिल्ली की स्थिति भी बेहतर नहीं–शहर की मुख्य जलधारा यमुना प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार है, जबकि भूजल स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में जा चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों में जलापूर्ति पूरी तरह समाप्त हो सकती है।

पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति भी चिंताजनक है। धान,गन्ने जैसी अत्यधिक जल-खपत वाली फसलों का विस्तार, सिंचाई तकनीकों का अल्प उपयोग और नगण्य वर्षा जल संचयन ने भूजल अंधाधुंध तरीके से समाप्त कर दिया। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा के 85 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर पार कर चुका है।

भारत में जल संकट के लिए जिम्मेदार केवल वर्षा की अनियमितता नहीं है, बल्कि जल निकायों पर अतिक्रमण, नीति असंगति, शहरी अपशिष्ट का जल स्रोतों में मिलना और लोगों में जल बचत के प्रति उदासीनता जैसे कारक भी उतने ही उत्तरदायी हैं।

जल संकट से निपटने के लिए कई योजनाएं तो बनाई गईं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कागजी आंकड़ों तक ही सीमित रह गया। मसलन, जल जीवन मिशन को सिर्फ हर घर नल तक सीमित समझा गया, जबकि उसका मूल उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों का सशक्तीकरण और सामुदायिक सहभागिता के जरिए जल आत्मनिर्भरता था।

इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी। जल को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर नागरिक सहभागिता पर बल देना होगा। जल संरक्षण को जीवनशैली में लाना होगा झ जैसे कैपटाउन में लोगों ने बर्तनों में नहाने का पानी जमा कर पौधों को सींचा, हाथ धोते समय नल बंद करना सीखा और शौचालयों में रिसाइकल पानी का प्रयोग शुरू किया।

भारत में भी प्रत्येक इमारत में वर्षा जल संचयन अनिवार्य करना चाहिए, जिसे स्थानीय निकाय सख्ती से लागू करें। भूजल का मापन, नियमन और पुनर्भरण एक समर्पित मिशन के तहत चलाया जाए। जल जीवन मिशन को स्थानीय स्रोतों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण पर केंद्रित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट की जगह परकोलेशन पिट्स, बायोस्वेल्स और हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे ताकि वर्षा जल भूमि में जज्ब हो सके। पानी की कीमत समझना और उपभोग पर नियंत्रण लाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए स्लैब आधारित मूल्य निर्धारण, जहां न्यूनतम जरूरतों के बाद अतिरिक्त खपत पर उच्च शुल्क लगे, एक व्यावहारिक नीति हो सकती है। इससे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग प्रोत्साहित होगा। वहीं, तकनीकी नवाचार जैसे जल रिसाव की स्मार्ट निगरानी, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और समुद्री जल से मीठा पानी बनाने की प्रक्रिया को प्रमुखता दी जानी चाहिए। चेन्नई ने समुद्री जल शोधन संयंत्र की ओर कदम बढ़ाया है, और यह उन तटीय शहरों के लिए प्रेरणा हो सकता है जहां भूजल या वर्षा जल अपर्याप्त है।

मराठी बोलना गर्व की बात, लेकिन हिन्दी से घृणा क्यों ?

अजय जैन विकल्प

अपनी स्थापना से ही भारत विविधताओं का देश बना हुआ है और भाषा इसकी सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। इसलिए यहाँ अनेकता के बावजूद एकता है, चाहे फिर कोई भी मुद्दा हो, यानी कभी अपने को श्रेष्ठ बताकर किसी अन्य को बुरा नहीं कहा गया, किन्तु इस देश के राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में फिलहाल यही बुरा देखा जा रहा है, जो अनुचित है और देश की भाषाई एकता के लिए घातक भी है।

मुम्बई न केवल आर्थिक राजधानी है, बल्कि भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों का संगम स्थल भी है। इस महानगर में मराठी का बोलबाला होना स्वाभाविक है, यह इस मिट्टी की आत्मा है, लेकिन आज एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर रही है:हिन्दी के प्रति अघोषित घृणा दिख रही है, जिसके पीछे असहिष्णुता, राजनीतिक विद्वेष एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताने की अजीब मानसिकता है। मराठी को सम्मान देने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपत्ति तब होती है, जब इस सम्मान के नाम पर हिन्दी को हाशिए पर धकेला जाता है, हिन्दी भाषियों को बाहरी करार दिया जाता है, और उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। यह केवल भाषाई टकराव नहीं, एक गहरी राजनीतिक साजिश है, जिसे समझना, उजागर करना और विरोध करते हुए हिन्दी के लिए खड़े रहना बहुत आवश्यक है। यह समझना होगा कि मराठी स्वाभिमान की भाषा है, लेकिन हिन्दी के प्रति संकीर्णता सही नहीं है। मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि सभ्यता, इतिहास और गौरव है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक आदि महापुरुषों ने मराठी को जनचेतना और क्रांति का माध्यम बनाया, तो कैद में रहते हुए भी राष्ट्रीय एकता के लिए वीर विनायक सावरकर ने हिन्दी कविताएं रचीं एवं हिन्दी सिखाई। आज भी महाराष्ट्र में मराठी साहित्य, नाटक, संगीत और संस्कृति की धारा बह रही है।

मराठी बोलना, मराठी में गर्व करना, उस विरासत को आगे बढ़ाना हर मराठीभाषी का हक और कर्तव्य है मगर जब यह गर्व दूसरों की भाषा के प्रति घृणा में बदल जाता है, तो यह स्वाभिमान नहीं, संकीर्णता बन जाता है।

सबको समझना पड़ेगा कि हिन्दी एकता का सेतु और मुम्बई का मौन आधार है। हिन्दी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो उत्तर भारत से लेकर भारत के कोने-कोने तक संवाद का माध्यम है। मुम्बई जैसे महानगर में हिन्दी केवल उत्तर भारतीयों की नहीं, बल्कि लाखों मराठी, गुजराती, बिहारी, तमिल, मलयाली और बंगालियों के भी दैनिक संवाद की भाषा बनी हुई है।

मुम्बई यानी बॉलीवुड सहित रेडियो, टेलीविजन, विज्ञापन, सेवा क्षेत्र और मीडिया के अधिकतर प्रमुख उद्योग हिन्दी के दम पर खड़े हैं। यही नहीं, लाखों मेहनतकश मजदूर, वाहन चालक, नौकर, घरेलू कामगार, उद्घोषक, पत्रकार और कलाकार भी हिन्दी के माध्यम से ही रोजी-रोटी व पहचान प्राप्त करते हैं, तो बड़ा सवाल है कि इस हिन्दी से इतनी घृणा क्यों, मारपीट क्यों, प्रदर्शन क्यों...?

स्थानीय राजनीतिक कारण देखें तो पता चलता है कि मराठी बनाम हिन्दी की कृत्रिम खाई बनाई गई है, क्योंकि उसी से तो सत्ता प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाषा का यह संघर्ष अचानक नहीं पनपा है, बल्कि यह कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम है। मराठी मानुस के नारे के पीछे वर्षों से एक अपराध-बोध और भय को बोया गया, कि हिन्दी भाषी मुम्बई को हड़प रहे हैं, जबकि सत्यता इससे अलग है और धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिन्दी बोलने वाला अपना काम कर रहा है, तो मराठी एवं अन्य भाषा बोलने वाला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। राज्य और मुम्बई को निगलने के ऐसे विचार न केवल झूठे हैं, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा हैं, क्योंकि मुम्बई की आत्मा में तो हिन्दी हमेशा रही है। १९५० के दशक में भी जब बम्बई राज्य बना था, तब भी हिन्दीभाषी इसके विकास में बराबरी से सहभागी थे।

हिन्दी को बाहरी भाषा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि संविधान में यह राजभाषा घोषित है और इसे पूरे भारत में समान सम्मान प्राप्त है। ऐसा भी लगता है कि असल डर हिन्दी से नहीं, बल्कि उस जनसांख्यिकी बदलाव से है, जो उत्तर भारत से आए श्रमिकों और युवाओं के कारण मुम्बई में हो रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा में गिरावट और स्थानीय युवाओं को नौकरियों नहीं मिलने का दोष भी हिन्दी भाषियों पर डाल देना आसान बहाना बन गया है, लेकिन इसका उचित समाधान खोजने की अपेक्षा हिन्दी को रोककर गुंडागर्दी करना कहाँ से सही हो गया है ? क्या हिन्दी भाषियों को निकाल देने से, हिन्दी नहीं बोलने देने से, राजनीति करने से एवं सिर्फ मराठी की जिद लगाने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा ? राज्य तरक्की कर लेगा, हिन्दी और मराठी का स्नेह बना रहेगा ?

उत्तर साफ है-नहीं, क्योंकि विकास की कुंजी भाषाओं को सीमित करने में नहीं, बल्कि उन्हें सर्वव्यापी व समावेशी बनाने में है। राजनीति के चक्कर में यह भूलना घातक है कि हिन्दी को अपमानित करना आसान है। वास्तव में यह संविधान का अपमान है, क्योंकि संविधान की धारा ३४३ हिन्दी को राजभाषा घोषित करती है। अनुच्छेद १९ हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो कोई भी राज्य, नगर या संस्था किसी भाषा विशेष को किसी को बोलने से कैसे रोक सकता है। मुम्बई में हिन्दी बोलने वाले पर तंज कसना, दुकानों के बोर्ड बदलवाना या हिन्दी में सेवा देने से इनकार करना सीधे तौर पर संविधान का सीधा उल्लंघन यानी राष्ट्रद्रोह है।

मुम्बई में हिन्दी का विरोध करने वालों एवं भाषा के बँटवारे पर मौन रहने वालों को भाषाई सौहार्द के उदाहरण दक्षिण भारत से सीख लेनी चाहिए। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी भाषाओं को मजबूत किया, लेकिन कभी हिन्दी को दुश्मन नहीं बनाया। बेंगलुरु जैसे शहर में भी कन्नड़ प्रमुख है, लेकिन हिन्दी स्वीकार है। वहाँ के लोग हिन्दी सीखते हैं, सिखाते हैं और साथ रहते हैं।

मुम्बई, जो देश का सबसे बड़ा समावेशी शहर कहलाता है, वहाँ से हिन्दी फिल्म और टी.वी. उद्योग निकाल दिया जाए, तो कल्पना करें कि क्या बचेगा ? अगर हिन्दी बोलने वाला अपने ही देश में पराया महसूस करे, तो यह केवल शर्मनाक नहीं, बड़ा जहर है।

सबको इस बात को महसूस करना होगा कि भाषाई टकराव से कुछ नहीं सधेगा। मराठी और हिन्दी दोनों समृद्ध भाषाएं हैं। दोनों में साहित्य, संस्कृति, ज्ञान और इतिहास की गहराइयाँ हैं। इसलिए कुछ सकारात्मक कदम एवं उदारता लेकर विद्यालयों में मराठी और हिन्दी दोनों को सम्मानजनक स्थान दिया जाए। सार्वजनिक बोर्डों में मराठी प्रमुख हो, लेकिन हिन्दी को न हटाया जाए। सरकार ऐसे कार्यक्रम चलाए, जो भाषाई सौहार्द को बढ़ावा दें। यानी नेता वोट बैंक के लिए भाषा को हथियार न बनाएं।

राजनीति से पनपाए गए इस विवाद का समाधान बनाम निष्कर्ष यही है कि मुम्बई की आत्मा मराठी और हिन्दी का संगम है, यानी मुम्बई केवल मराठी या हिन्दी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की है। जैसे कश्मीर भारत का स्वर्ग है, ऐसे ही महाराष्ट्र और मुम्बई का असली सौंदर्य विविधता-अनेकता में है। हिन्दी से घृणा करके हम न तो मराठी को मजबूत कर सकते हैं, न मुम्बई को।

मराठी और हिन्दी २ भाषाएं नहीं, २ आत्माएं हैं-जिन्हें जोड़कर ही भारत एकता और शक्ति की मिसाल बनेगा। कारण कि किसी भी भाषा से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा से घृणा करना अपने ही देश और उसके नियम-कायदों से घृणा करने जैसा है।

यह भी तय है कि मुम्बई और राज्य के अन्य हिस्सों में मराठी बनाम गैर-मराठी भाषा विवाद को लेकर चल रहे राजनीतिक और सामाजिक तनाव, प्रदर्शन, गुंडागर्दी और जबरदस्ती से भाषा एवं क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा हल नहीं होगा, बल्कि इससे आमजन के बीच विश्वास घटकर विष फैलेगा। बेहतर यह है कि सरकार और सभी को राज्य-देश हित में इस घमासान को टालते हुए देशप्रेम दिखाकर दोनों भाषा का सम्मान स्वीकारना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद

भारत में मुख्यधारा का मीडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सलाह मानते हुए अब सकारात्मक रवैया अपनाने लगा है, खासकर तब, जबकि इसमें किसी भी तरह भाजपा का हित जुड़ा हो। प्रधानमंत्री बनने से पहले दिल्ली में कॉलेज छात्रों को दिए एक भाषण में अपनी सकारात्मक सोच का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा था कि वे गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, इस सवाल पर कहते हैं कि गिलास पूरा भरा है, जो खाली दिख रहा है, वहां हवा भरी है। तो बस तब से देश में ऐसे ही हवा-हवाई माहौल चल रहा है। कुछ रहे न रहे, बस सब चंगा सी की उम्मीद पर देश को चलाया जा रहा है। मीडिया भी तथ्यों को न देखकर हवा-हवाई बातों को बढ़ा रहा है। जैसे गुरुवार को मीडिया ने इस बात को जोर-शोर से चलाया कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग की बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण की कवायद पर शीर्ष अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन ये हवा से आधे भरे गिलास का उदाहरण है। असल बात ये है कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वह जिन 11 दस्तावेज की मांग मतदाताओं से कर रहा है, उसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी कहा है कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह गृहमंत्रालय का विषय है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों और तर्कों के आधार पर

ही सुनवाई होने दी और उसकी अहम टिप्पणियां भी इन्हीं के आधार पर थीं। सुप्रीम कोर्ट न पूरी तरह चुनाव आयोग के पक्ष में दिखा, न उसने याचिकाकताओं की तरफ कोई पक्षपात दिखाया, बल्कि उसकी तटस्थता साफ नजर आई, फिर भी मीडिया में चलाए जा रहे शीर्षक यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहार में जिस मुद्दे को लेकर 9 जुलाई को विपक्ष ने इतना बड़ा हल्ला बोल किया, उस मुद्दे पर विपक्ष को अदालत में झटका मिला है। जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की कवायद शुरू की और इसके लिए केवल एक महीने का ही वक्त मतदाताओं को दिया कि वे अपने नागरिक होने का प्रमाण खुद ही पेश करें। आयोग ने 11 दस्तावेज की सूची जारी की और कहा कि इनमें से किसी को पेश करने पर ही किसी का नाम मतदाता सूची में आएगा, अन्यथा काट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं से खुद के नागरिक होने का सबूत मांगा, जबकि इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दी, जबकि करोड़ों गरीबों के पास यही सबसे सुलभ पहचानपत्र होते हैं और इन्हें भी सरकार ही जारी करती है। इस फैसले को लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला करते हुए चुनाव आयोग के समक्ष विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया था, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद करवाया और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अलावा राजद सांसद मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल, राकांपा (शरद पवार गुट) की सुप्रिया सुले, भाकपा के डी. राजा, सपा के हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के अरविंद सावंत, झामुमो के सरफराज अहमद, और भाकपा (माले) के दीपंकर भट्टाचार्य, इन सभी ने शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इस विशेष गहन पुनरीक्षण में कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगभग 7.9 करोड़ नागरिकों को कवर करेगी, और इसमें वोटर आईडी और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। याचिकाकेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है जबकि यह काम चुनाव आयोग का है।

उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि वह 30 दिनों में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। इस मामले में गुरुवार को पहली सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले में सुनवाई की। बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि आधार कार्ड को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। जिस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने जवाब दिया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तब जस्टिस धूलिया ने कहा, लेकिन नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि आयोग को अनुच्छेद 326 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। वहीं जस्टिस बागची ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर आपका निर्णय यह है कि 2025 की मतदाता सूची में पहले से दर्ज व्यक्ति को भी मताधिकार से वंचित किया जाए, तो उस व्यक्ति को अपील करनी होगी, पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा और अंततः आगामी चुनाव में मतदान का अधिकार छिन जाएगा। आप मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच कर सकते हैं ताकि गैर-नागरिक सूची में न रहें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप यह कार्य प्रस्तावित चुनाव से कुछ ही महीने पहले शुरू करते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन आयोग को तीन दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार करने का सुझाव दिया है।

सांप: रहस्य नहीं, समझ का विषय हैं वे

सांपों को लेकर मानव समाज में आदिकाल से ही रहस्य, भय और अंधविश्वास जुड़ते चले आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में सांप केवल एक जीव नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रतीकों से जुड़ा हुआ नाम है। नाग देवता की पूजा से लेकर लोक कथाओं, परंपराओं और फिल्मों तक, सांप को कभी आराध्य रूप में तो कभी खलनायक के रूप में देखा गया है। लेकिन इस भावनात्मक और काल्पनिक दृष्टिकोण से अलग, अगर हम सांपों को वास्तविकता और वैज्ञानिक समझ के साथ देखें, तो एक बिलकुल अलग तस्वीर सामने आती है एक ऐसी तस्वीर जिसमें सांप न भयावह हैं, न रहस्यमयी, बल्कि प्रकृति की एक अद्भुत और आवश्यक रचना हैं।

धरती पर सांपों की लगभग 3,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में करीब 300 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से भी केवल कुछ ही प्रजातियाँ विषैली होती हैं, जैसे कि कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जिन्हें बिग फोर कहा जाता है। शेष अधिकांश सांप निरपराध और मानव के संपर्क से बचने वाले जीव हैं। लेकिन डर और अज्ञानता के चलते अक्सर हर सांप को खतरनाक समझा जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, चाहे वह विषैला हो या नहीं। वास्तव में, सांप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। वे खेतों और घरों में चूहों व अन्य कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जो फसलों और खाद्यान्न को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि सांप न हों, तो यह असंतुलन खाद्य श्रृंखला में भारी विघटन ला सकता है। उनके बिना हमारी जैव विविधता अधूरी है। सांपों का शरीर बिना पैरों के होते हुए भी अत्यंत लचीला, तेज और पर्यावरण के अनुकूल होता है। वे जंगलों, खेतों, रेगिस्तानों, पर्वतों और यहाँ तक कि बर्फीले इलाकों में भी जीवित रह सकते हैं। उनकी खाल समय-समय पर झड़ती है, जिसे कुछ परंपराओं में नवजीवन या पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में शेषनाग, वासुकी और अनंत जैसे नागों की कथाएँ आज भी जीवंत हैं। भगवान विष्णु के शयन के आसन से लेकर शिव के गले में लिपटे वासुकी तक, सांपों को ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। नागपंचमी जैसे पर्व, नाग मंदिरों की स्थापना और नाग-कथाओं की समृद्ध परंपरा इस सांप-मानव संबंध को एक पवित्र आयाम देती हैं। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में यह आवश्यक हो गया है कि हम सांपों को केवल पौराणिक या रहस्यमयी दृष्टि से नहीं, बल्कि विवेक और तथ्य की दृष्टि से भी समझें। दुर्भाग्यवश, हिंदी फिल्मों, लोक कथाओं और टेलीविजन धारावाहिकों ने सांप को प्रतिशोध लेने वाले जीव के रूप में चित्रित किया है। कहा जाता है कि साँप अपनी मादा की हत्या का बदला लेते हैं, किसी की तस्वीर अपनी आँखों में कैद कर लेते हैं और वर्षों बाद भी शत्रु को पहचान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि साँप न तो इंसान को शिकार मानते हैं, न ही उन्हें कोई प्रतिशोध भाव होता है। वे केवल तभी काटते हैं जब उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। यानी, काटना उनका रक्षात्मक व्यवहार है, आक्रामक नहीं।

अब समय आ गया है कि हम सांपों के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाएँ। देश में कई संस्थाएँ कार्यरत हैं जो सांपों की पहचान, संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना बेहद आवश्यक है कि कौन से सांप विषैले होते हैं, उनके काटने पर क्या करना चाहिए, और किस प्रकार हमें उनसे डरने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। जब ज्ञान भय का स्थान लेगा, तभी सह-अस्तित्व की भावना उत्पन्न होगी। सांप न तो हमारे शत्रु हैं, न देवता।

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

-ललित गर्ग-

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करना चाहिए।

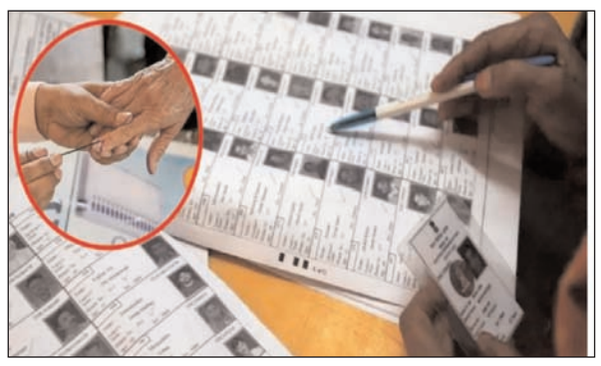

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्वेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, आखिर क्यों? बिहार में एसआईआर को लेकर जो याचिकाएं और बहसें सामने आईं, उनमें एक प्रमुख तर्क यह था कि समय उपयुक्त नहीं है, सरकार अस्थिर है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्युमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अग्निपथ योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए।

यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि जो सरकार करे, उसका विरोध करो, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ?

क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति इस बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं।

तुर्की की अदालत ने एलन मस्क के एआई चैटबॉट 'ग्रोक' पर लगाया प्रतिबंध, राष्ट्रपति और अतातुर्क पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप

अंकारा। तुर्की की एक आपराधिक अदालत ने देश में एलन मस्क के एआई चैटबॉट 'ग्रोक' पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब चैटबॉट पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन, उनकी दिवंगत मां और आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क सहित अन्य प्रमुख हस्तियों के विरुद्ध आपत्तिजनक और अपमानजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगा। सरकारी समर्थक टीवी चैनल 'ए हैबर' और अन्य मीडिया संस्थानों के अनुसार, यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया मंच एक्स पर उपयोगकर्ताओं के सवालों के जवाब देते हुए ग्रोक ने तुर्की के नेताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। इस घटना के बाद अंकारा की जनता ने तुर्की के इंटरनेट कानून के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोपों के साथ अदालत में शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए तुर्की की दूरसंचार प्राधिकरण को 'ग्रोक' पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इस विवाद के बीच, एक्स और मस्क की एआई कंपनी एक्स-एआई ने स्थिति को संभालने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने कहा, हमने आपत्तिजनक पोस्टों को हटाया है और ग्रोक द्वारा एक्स पर किसी भी प्रकार के हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं।

अमेरिका से निर्वासित आठ लोग दक्षिण सूडान की निगरानी में, सिर्फ एक है सूडानी नागरिक

जुबा। युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान सरकार ने पुष्टि की है कि अमेरिका से विवादास्पद रूप से निर्वासित आठ लोगों को उसकी निगरानी में रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि इन आठ में से सिर्फ एक व्यक्ति ही दक्षिण सूडान का नागरिक है, जबकि शेष में म्यांमार, क्यूबा, वियतनाम, लाओस और मैक्सिको के नागरिक शामिल हैं। दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये सभी फिलहाल जुबा में संबंधित अधिकारियों की देखरेख में हैं, जहां उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह कदम अमेरिका के अनुरोध पर सावधानीपूर्वक और विचारपूर्ण निर्णय के तहत उठाया गया है। बयान में आगे कहा गया, यह फैसला मानवीय सहयोग और परस्पर हितों की प्रतिबद्धता के रूप में लिया गया है। हालांकि इस कदम को लेकर देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता जताई जा रही है। प्रख्यात नागरिक कार्यकर्ता एडमंड याकानी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दक्षिण सूडान अपराधियों के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त 11 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता, जहां उसके जीवन, स्वतंत्रता या शारीरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हो।

इटली सरकार यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लघु एवं मध्यम उद्यमों को देगी 300 मिलियन यूरो की सहायता

रोम। इटली सरकार ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भाग लेने वाले अपने देश के लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए 300 मिलियन यूरो (लगभग 2,700 करोड़ रुपये) की विशेष सहायता योजना पेश करने की घोषणा की है। इस योजना की घोषणा इटली के विदेश मंत्री एंतोनियो तजानी ने की। यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब रोम में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 90 देशों के 4,000 से अधिक प्रतिनिधि, भाग लेने वाले हैं,जिनमें 50 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। विदेश मंत्री तजानी ने कहा, यह सहायता योजना न केवल इटली के व्यापारिक समुदाय को वैश्विक भूमिका निभाने का अवसर देगी, बल्कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पुनर्निर्माण में भी हमारी नैतिक और आर्थिक प्रतिबद्धता को दर्शाएगी। यह सहायता पैकेज उन इटालियन कंपनियों को मिलेगा, जो युद्ध से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में भाग लेंगी।

शेख हसीना को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी: बीएनपी

ढाका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने आज कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके साथियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। यह सभी सामूहिक हत्याओं, यातनाओं और लोगों पर फासीवादी हमलों में शामिल हैं। हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग फासीवाद समर्थक हैं। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, बीएनपी नेता फखरुल ने राजधानी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज एंड हॉस्पिटल में बीएनपी अध्यक्ष की सलाहकार परिषद के सदस्यों डॉ. अब्दुल कुद्दुस और डॉ. सिराजुद्दीन से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह टिप्पणी की। पत्रकारों ने बीबीसी वर्ल्ड की विशेष रिपोर्ट बांग्लादेश के लिए लड़ाई- शेख हसीना का पतन पर उनकी टिप्पणी मांगी, तो फखरुल ने कहा कि सामूहिक हत्याओं और दमन में शामिल हर व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए और न्याय का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की हत्या के लिए शेख हसीना पूरी तरह जिम्मेदार हैं। बीएनपी नेता ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी को मिला नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

एजेंसी

विंडहोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विस्चिया मिराबिलिस' से नवाजा गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 27वां अंतरराष्ट्रीय और उनकी वर्तमान में जारी पांच देशों की यात्रा के दौरान चौथा सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह ने आज सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री को इससे नवाजा। सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने सम्मान को दोनों देशों को समर्पित किया और साथ मिलकर निरंतर प्रगति और विकास के लिए काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है और इसे वे 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वीकार कर रहे हैं। संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने

नामीबिया के दुनिया के सबसे बड़े हीरा उत्पादन देश और भारत के सबसे बड़े पॉलिशिंग उद्योग देश होने का संदर्भ दिया और भविष्य की साझेदारी में विश्वास को दोहराया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी साझेदारी भी इन हीरों की तरह चमकेगी। नामीबिया की आजादी के कुछ सालों के बाद 1995 में इस सम्मान की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य विशिष्ट सेवा और नेतृत्व का सम्मान देना है। इसका नाम वेल्विस्चिया मिराबिलिस के नाम पर रखा गया है। यह नामीबिया का एक प्राचीन रेगिस्तानी पौधा है। नामीबियाई लोगों के लचीलेपन, दीर्घायु और स्थायी भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने सम्मान से जुड़े प्रतीकात्मक अर्थ का उल्लेख किया और कहा कि वेल्विस्चिया पौधे को नामीबियाई लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और यह समय के बीतने के साक्षी परिवार के बुजुर्गों के समान है। मैत्री और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और नामीबिया के बीच ऐतिहासिक मित्रता पर जोर दिया। उन्होंने सम्मान को भारत और नामीबिया की चिरस्थायी मैत्री का साक्षी बताया। उन्होंने कहा कि एक सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। भारत और नामीबिया अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।

ट्रंप पर पिछले साल हुई गोलीबारी की घटना में छह सीक्रेट सर्विस एजेंट निलंबित

एजेंसी

वाशिंगटन। पिछले साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर की गई गोलीबारी की घटना के संबंध में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने छह एजेंटों को निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले साल 13 जुलाई को पेंसिलवेनिया के बटलर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से जुड़ी विफलताओं के सिलसिले में की गई है। एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, 13 जुलाई, 2024 को हुई गोलीबारी की घटना की बरसी से चार दिन पहले ही इन कर्मियों के निलंबन की पुष्टि की गई है। इस गोलीबारी में ट्रंप का कान खून से लथपथ हो गया था। ट्रंप की इस चुनावी रैली में हुई गोलीबारी में अग्निशमनकर्मी कोरी कॉम्पेरेटोरे की हमले में मौत हो गई थी। रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर्स ने शूटर को मार गिराया था। उसकी पहचान एफबीआई ने 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में की थी। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने गोलीबारी की घटना की जांच की। इसमें साफ हुआ कि कानून प्रवर्तन की कई खामियों का फायदा मैथ्यू ने उठाया। जांच में कहा गया कि सीक्रेट सर्विस अपने महत्वपूर्ण मिशन में विफल रही। उल्लेखनीय है कि गोलीबारी की घटना के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दे दिया था। निलंबित किए गए एजेंटों को अपील करने का अधिकार दिया गया है। निलंबित एजेंटों में कुछ अधिकारी भी हैं। बटलर में गोलीबारी की घटना के ठीक नौ हफ्ते बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित गोल्फ कोर्स में भी ट्रंप पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ था।

लॉस एंजिल्स में सुरंग ढही, अग्निशमन कर्मियों ने 31 श्रमिकों को बचाया

एजेंसी

वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के खूबसूरत शहर लॉस एंजिल्स में एक सुरंग ढह गई। इस दौरान सुरंग में कम से कम 31 श्रमिक काम कर रहे थे। इन सभी को बचा लिया गया है। लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया प्रांत का सबसे बड़ा एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लॉस एंजिल्स मनोरंजन उद्योग, हॉलीवुड, और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर दुनिया भर में मशहूर हस्तियों, फिल्म, टेलीविजन, और जीवंत सांस्कृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। सीबीएस न्यूज चैनल के अनुसार, लॉस एंजिल्स अग्निशमन विभाग ने बताया कि शहर के विलमिंगटन क्षेत्र में हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। निर्माणाधीन यह सुरंग अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है। विलमिंगटन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉस एंजिल्स काउंटी पर्यवेक्षक जेनिस हैन ने कहा कि सुरंग के अंदर मौजूद श्रमिकों को घटना के लगभग

एक घंटे बाद बचा लिया गया। अग्निशमन विभाग के अनुसार, सुरंग में फंसे 31 निर्माण श्रमिकों में से किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। इन श्रमिकों को लगभग 12 से 15 फुट ऊंचे मिट्टी के ढेर से सुरक्षित निकाला गया। मेयर करेन बास ने कहा कि उन्होंने इन श्रमिकों से बातचीत की है। सभी ने अग्निशमन विभाग का आभार जताया है। बास ने कहा कि अग्निशमन कर्मी लॉस एंजिल्स के सच्चे नायक हैं। लॉस एंजिल्स अग्निशमन विभाग ने कहा कि सुरंग ढहने की सूचना रात 7:58 बजे मिली। तत्काल शहर की सभी खोज और बचाव टीमों को साउथ फिगेरोआ स्ट्रीट के 1700 ब्लॉक में संसाधन के साथ भेजा गया। सुरंग का यह हिस्सा प्रवेश द्वार से छह मील दूर हुआ। 630.5 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत वाली एफ्लुएंट आउटफॉल सुरंग लॉस एंजिल्स काउंटी सैनिटेशन डिस्ट्रिक्ट के क्लियरवाटर प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

ट्रंप की आलोचना करने पर एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी का सीक्रेट सर्विस ने पीछा किया

एजेंसी

वाशिंगटन। एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करना भारी पड़ सकता है। इस बीच खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया में ट्रंप की आलोचना करने वाली पोस्ट सामने के बाद जेम्स कॉमी का सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने पीछा किया। कॉमी ने सोशल मीडिया पर 86 47 लिखे सीपों की एक तस्वीर पोस्ट की थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, सादे लिबास में सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने बिना नंबर वाली कारों से उनका पीछा किया। यही नहीं उनके सेलफोन को भी ट्रैक किया। राष्ट्रपति ट्रंप के सहयोगियों ने कॉमी की पोस्ट पर कहा था कि यह एक तरह से हत्या की धमकी दी गई है। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने जब कॉमी का पीछा किया तो वह अपनी पत्नी पैट्रिस के साथ उत्तरी कैरोलिना तट के आसपास छुट्टियां मनाने में मशगूल थे। एजेंटों ने उनका वर्जीनिया से वाशिंगटन तक पीछा किया। अमेरिकी समाचार पोर्टल स्पेक्ट्रम

लोकल न्यूज 1 के अनुसार, न्याय विभाग के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि पूर्व सीआईए निदेशक जॉन ब्रेनन और पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी के खिलाफ जांच चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ सांसदों ने न्याय विभाग की इस पुष्टि पर खुशी जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पांच अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से ब्रेनन और कॉमी को बेईमान और बेहद भ्रष्ट अधिकारी बताया। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के 2016 के चुनाव अभियान के दौरान इन दोनों अधिकारियों ने उनके रूस के साथ रिश्तों की जांच की थी। ट्रंप ने कहा कि इन दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

एनबीसी न्यूज, फॉक्स न्यूज, सीएनएन और द वाशिंगटन टाइम्स की खबरों से संकेत मिल रहा है कि ब्रेनन और कॉमी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने पर विचार किया जा रहा है।

आईएमओ की बैठक में भारत ने उठाया कंटेनर शिप सुरक्षा और लैंगिक समानता का मुद्दा

एजेंसी

लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चल रही अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद के 134वें सत्र में भारत ने समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समावेशिता जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भारत के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अहम बैठक में हिस्सा लिया और कई जरूरी पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया। सत्र के पहले दिन भारत ने हाल ही में भारतीय जलक्षेत्र में विदेशी ध्वज वाले कंटेनर जहाजों से जुड़ी समुद्री घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। इन घटनाओं में अघोषित खतरनाक सामान और जहाजों की संरचनात्मक कमजोरियों के चलते सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। भारत ने आईएमओ से मांग की कि इन घटनाओं की गहराई से जांच की जाए

और कंटेनर शिपिंग के सुरक्षा ढांचे में जल्द सुधार किए जाएं। साथ ही लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक माल की पैकेजिंग, घोषणा और निगरानी के लिए सख्त अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर भारत ने समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने आईएमओ से अपील की कि वह इस तरह की घटनाओं की गहन वैश्विक समीक्षा शुरू करे ताकि भविष्य में समुद्री सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही भारत ने लैंगिक समानता को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। आईएमओ की लैंगिक समावेशन रणनीति के तहत भारत ने सागर में सम्मान नामक अपनी राष्ट्रीय पहल का जिक्र किया, जिसे 25 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिकाओं में भी अवसर देना है। भारत ने गर्व के साथ बताया कि देश में महिला नाविकों की संख्या में 650 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आईएमओ के समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समुद्री समुदाय के समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता रहेगा।

ट्रंप पर पिछले साल हुई गोलीबारी की घटना में छह सीक्रेट सर्विस एजेंट निलंबित

एजेंसी

वाशिंगटन। पिछले साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप पर की गई गोलीबारी की घटना के संबंध में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने अपने छह एजेंटों को निलंबित कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई पिछले साल 13 जुलाई को पेंसिलवेनिया के बटलर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास से जुड़ी विफलताओं के सिलसिले में की गई है। एबीसी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार, 13 जुलाई, 2024 को हुई गोलीबारी की घटना की बरसी से चार दिन पहले ही इन कर्मियों के निलंबन की पुष्टि की गई है। इस गोलीबारी में ट्रंप का कान खून से लथपथ हो गया था। ट्रंप की इस चुनावी रैली में हुई गोलीबारी में अग्निशमनकर्मी कोरी कॉम्पेरेटोरे की हमले में मौत हो गई थी। रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर्स ने शूटर को मार गिराया था। उसकी पहचान एफबीआई ने 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में की थी। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने गोलीबारी की घटना की जांच की। इसमें साफ हुआ कि कानून प्रवर्तन की कई खामियों का फायदा मैथ्यू ने उठाया। जांच में कहा गया कि सीक्रेट सर्विस अपने महत्वपूर्ण मिशन में विफल रही। उल्लेखनीय है कि गोलीबारी की घटना के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम्बर्ली चीटल ने इस्तीफा दे दिया था। निलंबित किए गए एजेंटों को अपील करने का अधिकार दिया गया है। निलंबित एजेंटों में कुछ अधिकारी भी हैं। बटलर में गोलीबारी की घटना के ठीक नौ हफ्ते बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित गोल्फ कोर्स में भी ट्रंप पर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना के बाद ट्रंप को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजयी रहे। उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला।

आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर दिया जोर

एजेंसी

काठमांडू। काठमांडू में नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर कॉपरेशन एंड इंगेजमेंट नामक गैर सरकारी संस्था द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया में आतंकवाद का प्रभाव संबंधी एक सेमिनार में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सेमिनार में उपस्थित वक्ताओं ने नेपाल को आतंकवाद का ट्रांजिट प्वाइंट बनने देने से रोकने के लिए सतर्कता बरतने और कुछ कड़े कानून लाने का सुझाव दिया। आयोजित सेमिनार में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने कहा कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान परस्त आतंकवाद अपनी जड़े जमा रहा है जो कि इस क्षेत्र की शांति एकता और अखंडता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विषय में किसी भी देश को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। थापा ने कहा कि यदि भारत में आतंकवादी हमला होता है तो

पड़ोसी होने के नाते हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह भारत में हुआ है और इसका हमसे क्या लेना-देना है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में होने वाले आतंकी हमला पर आज हम चुप बैठे तो अगला शिकार हम खुद होने वाले हैं इसलिए नेपाल को विश्व में कहीं भी होने वाले आतंकी हमले का कड़ा विरोध तो करना ही चाहिए और आवश्यकता हो तो उसमें साथ भी देना चाहिए।पूर्व विदेश मंत्री एनपी साउद ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए नेपाल ट्रांजिट प्वाइंट बनता जा रहा है यह चिंता की बात है। काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण की घटना हो या मुंबई-दिल्ली (भारत) में हुए आतंकी हमले में नेपाल का कनेक्शन यह दिखाता है कि नेपाल की भूमि का प्रयोग कर आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकवाद नेपाल में अपनी जड़े नहीं जमाए इसके लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि नेपाल में कभी दाऊद गिरोह सक्रिय रहता है तो कभी लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिद्दीन अपना सेल्टर बनाता है जो कि सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि नेपाल के लिए भी खतरा है। नेपाल को आतंक के साए से महफूज रखने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल ने इस संबंध में सतर्कता नहीं अपनाई और कड़े कानून नहीं बनाए तो आने वाले दिन में आतंक के साए से हम बच नहीं सकते हैं। एनपी साउद का कहना है कि नेपाल को आतंक पर अपना स्टैंड स्पष्ट रखना चाहिए। आतंकी हमला भारत में हो या इजराइल में, अमेरिका में हो या यूरोप में हर बार हमारा स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ ही होना चाहिए। देश देखकर हमें इस पर अपने आपको नहीं बदलना चाहिए।

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की दोबारा गिरफ्तारी को कोर्ट की मंजूरी, मार्शल लॉ से जुड़े मामले में नया मोड़

एजेंसी

सियोल। दक्षिण कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार तड़के देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की दोबारा गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी। यह गिरफ्तारी दिसंबर में उनके द्वारा थोड़े समय के लिए लगाए गए मार्शल लॉ से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर की गई है। अदालत ने विशेष अभियोजक की उस दलील को स्वीकार किया कि यून सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।यून सुक-योल को राजधानी सियोल के पास स्थित एक डिटेंशन सेंटर में फिर से भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मार्च में उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया था, जब अदालत ने जनवरी में उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर ट्रायल के दौरान हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं मानी थी। पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ जांच की कमान विशेष अभियोजक चो यून-सुक की टीम संभाल रही है, जो उन पर राजद्रोह, सत्ता के दुरुपयोग, सरकारी कामकाज में बाधा और आधिकारिक दस्तावेजों की हेराफेरी जैसे गंभीर आरोपों में नए मुकदमे दर्ज करने की तैयारी में है। टीम ने यून से दो बार पूछताछ करने के बाद रविवार को गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन दायर किया था। यून के वकीलों ने इसे अत्यधिक और निराधार बताया था, लेकिन अदालत ने गिरफ्तारी को जायज ठहराया। यून को शुरुआती तौर पर 20 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। यदि नए आरोपों में अभियोग तय होते हैं, तो वह 6 महीने तक हिरासत में रह सकते हैं। इस दौरान अदालत प्रारंभिक सुनवाई करेगी। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल की सजा सुनाई जा सकती है, जिसके बाद मामला उच्च अदालतों तक जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यून ने पिछले साल 03 दिसंबर को यह कहते हुए मार्शल लॉ घोषित किया था, कि उनके राष्ट्रविरोधी उदारवादी विरोधी उनकी नीतियों को बाधित कर रहे हैं। लेकिन यह कदम केवल कुछ ही घंटों में समाप्त हो गया जब सांसदों ने सैनिकों की नाकाबंदी तोड़कर संसद में प्रवेश किया और मार्शल लॉ रद्द करने के लिए मतदान किया।

इसके बाद, 14 दिसंबर को यून को महाभियोग के जरिए सत्ता से हटा दिया गया और 26 जनवरी को उन्हें राजद्रोह का आरोपित बनाते हुए अभियोग दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने संसद और चुनाव कार्यालयों को जबरन अपने नियंत्रण में लेने तथा राजनीतिक विरोधियों को कैद करने की योजना बनाई थी।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने रूस को एमएच17 हादसे और यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघनों का दोषी ठहराया

स्ट्रासबर्ग/द हेग। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में रूस को यूक्रेन में युद्ध अपराधों और 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच17 को मार गिराने का दोषी ठहराया है। यह फैसला यूक्रेन और नीदरलैंड द्वारा दायर चार प्रमुख मामलों पर आया है, जिनमें रूस पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के गंभीर उल्लंघनों के आरोप लगे थे। अदालत ने अपने 501 पन्नों के विस्तृत फैसले में कहा कि रूस की सैन्य कार्रवाइयों ने यूक्रेन में न केवल हत्याएं, यातनाएं, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों को जन्म दिया, बल्कि जानबूझकर नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया। अदालत के अध्यक्ष मैटियास गायोमार ने कहा, रूसी सैन्य बलों द्वारा किए गए हमलों ने हजारों नागरिकों की जान ली, उन्हें घायल किया और देश भर में भय और आतंक का माहौल पैदा किया। अदालत ने विशेष रूप से यह रेखांकित किया कि रूस ने यौन हिंसा को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा कि युद्ध के दौरान बलात्कार का प्रयोग एक अमानवीय अत्याचार है, जो यातना के समकक्ष है। अदालत ने 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 को मार गिराने के लिए भी रूस को जिम्मेदार ठहराया।

इस साल के अंत तक नामीबिया में यूपीआई सेवाएं शुरु होंगी, दो समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

एजेंसी

विंडहोक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। इसके बाद भारत और नामीबिया के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा नामीबिया सीडीआरआई और जीबीए जैसी अंतरराष्ट्रीय पहलों से जुड़ेगा। साथ ही घोषणा की गई कि इस साल के अंत तक नामीबिया में यूपीआई सेवाएं शुरु होंगी। नामीबिया की राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नामीबिया की राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवाह के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों नेताओं की उपस्थिति में करारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच हुए करारों के तहत नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त नामीबिया ने सीडीआरआई (इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंस) और ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस में शामिल होने की स्वीकृति पत्र सौंपे। दोनों देश डिजिटल नवाचार की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। भारत के यूपीआई

प्रौद्योगिकी के पिछले साल हुए लाइसेंसिंग समझौते के परिणामस्वरूप इस साल के अंत तक नामीबिया में डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, खनिज संसाधन, रक्षा सहयोग, डिजिटल शिक्षा, हाइड्रोकार्बन, सिविल न्यूक्लियर और पेट्रोलियम क्षेत्र जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा और उन्होंने आज अपनी वार्ता के दौरान भारत-नामीबिया संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर हमारी चर्चा में प्रमुखता से चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति नंदी-नदैतवाह ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विज़िटर बुक में हस्ताक्षर कर अपने विचार भी व्यक्त किए। प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रीय स्मारक 'हीरोज एकर' पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मारक देश के लिए बलिदान देने वालों के सम्मान में बनाया गया है। मुख्य तौर पर यह नामीबिया के संस्थापक डॉ. सैम नुजोमा को समर्पित है। डॉ. सैम नुजोमा ने नामीबिया को साल 1990 में दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई थी। वे देश के पहले राष्ट्रपति बने और 15 सालों तक इस पद पर रहे। इसी साल फरवरी में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

न्यूज फ्लैश

ओती आश्रम में भंडारे के बाद हुआ पौधरोपण

फतेहपुर। ओती गांव स्थित चुकरिहा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें जिलेभर के विभिन्न आश्रमों से पहुंचे साधु संतों ने प्रवचन व भजनों का आयोजन किया गया। सुबह नौ बजे से हवन पूजन करने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के बाद आश्रम पर में सभी लोगों द्वारा एक-एक पौधरोपण किया गया। आयोजक तेज बहादुर सिंह चैहान, विजय श्री फिलिंग स्टेशन जमेनी के मालिक राघवेन्द्र सिंह चैहान उर्फ प्रिंस, मंडल अध्यक्ष संजय सिंह, उमाकांत पांडेय, रीशू सिंह गौतम, मुन्नीलाल गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, अखिलेश तोमर, रामू सिंह परिहार, आदेश सिंह, कक्कू भैया, भानू प्रताप सिंह, बद्री विशाल सिंह, दादू मास्टर साहब सहित हजारों की तादात में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

बिजली बिल संबंधी समस्याओं के लिए होगा मेगा कैंप का आयोजन

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली बिल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया है कि विभाग समस्त उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें सही बिल निर्गत करना, नई बिलिंग एजेंसी को अबद्ध करना, और मीटर रीडिंग में ओसीआर एवं डाउनलोड कर सकने योग्य बिलिंग व्यवस्था शामिल है। बावजूद इन प्रयासों के, बड़ी संख्या में गलत बिल संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इसे देखते हुए पूरे प्रदेश में मेगा कैम्प आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये कैम्प 17, 18 और 19 जुलाई 2025 को प्रत्येक वितरण खंड में आयोजित किए जाएंगे। इन कैम्पों में शिकायतों का पंजीकरण 1912 हेल्प डेस्क पर सुनिश्चित किया जाएगा और शिकायतकर्ता का सही विवरण अंकित किया जाएगा। इन कैम्पों में उपभोक्ताओं को अपनी बिजली बिल संबंधी शिकायतों का निवारण करने में मदद मिलेगी। बताया कि प्राप्त शिकायतों के सापेक्ष बिल रिवीजन हेतु कार्यवाही एक सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में बिना शिकायत पंजीकृत और रसीद उपलब्ध कराए उपभोक्ता को वापस नहीं भेजा जाएगा।

कस्बे में अधिवक्ता संघ ने बुजुर्ग कांग्रेसी का माल्यार्पण किया स्वागत

बिंदकी, फतेहपुर। 40 सालों से कांग्रेस पार्टी में सेवाभाव से काम

कर रहे बुजुर्ग कांग्रेसी राम शंकर शुक्ला को अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत करते हुए मिष्ठान का वितरण किया। देवमई ब्लाक के गांव करचलपुर निवासी राम शंकर शुक्ल पिछले चालीस सालों से कांग्रेस से जुड़े हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कांग्रेस से ही निष्ठा बनाये रखी। श्री शुक्ल 25 साल मण्डल अध्यक्ष रहे। कांग्रेस जिला कमेटी ने संगठन में उपाध्यक्ष भी मनोनीत किया। जिलाध्यक्ष महेश द्विवेदी ने नव गठित कार्यकारिणी में राम शंकर शुक्ला को जिला सचिव मनोनीत किया। शुक्रवार को अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बिंदकी राजेंद्र मिश्र ने मनोनीत सचिव फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके कुलदीप, विकास शुक्ला, अनिल आदि मौजूद रहे।

सीओ चकबंदी के पत्थरगडी हटाने के मनमाने आदेश की डीएम से शिकायत

फतेहपुर। भूमिधरी भूमि पर सीओ चकबन्दी के पत्थर उखाडे जाने के मनमाने आदेश की शिकायत पीड़ित किसान ने डीएम से की है। डीएम ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खागा कोतवाली क्षेत्र के कस्बा सोहन निवासी मुंशीलाल ने बताया कि गाटा सं0 402 भूमिधरी भूमि है। जिसमें वह 1/3 का हिस्सेदार है। भूमि की पैमाइस सीओ के आदेश पर सहायक चकबन्दी अधिकारी व कानूनगो, लेखपाल द्वारा की जा चुकी है। उसी पैमाइस के अनुसार चकबन्दी अधिकारियों द्वारा सभी हिस्सेदारों के हिस्से की भूमि पर पत्थरगडी भी करा दी गई थी, सभी हिस्सेदार अपने-अपने हिस्से में काबिज व दाखिल है।

बावजूद इसके सीओ चकबन्दी ने मनमाने तरीके से मेरे पारिवारिक हिस्सेदारों से एक प्रार्थना पत्र लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो को पत्थर उखाड़ने के आदेश दिए हैं। सीओ चकबन्दी द्वारा अनुचित और अन्यायपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। जो पूरी तरह से गलत है। जिससे परिवार भूमिहीन हो जायेगा भूखो मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। पीड़ित ने डीएम से मांग की है कि सीओ चकबंदी के मनमाना आदेश पर रोक लगाते हुए जो जहां काबिज है उस पर काबिज रहने दिया जाए।

जीएसटी के नियमों से परेशान फूड व्यापारियों ने सीएम रेखा से की मुलाकात

दिव्य दिल्ली : इस संदर्भ में फूड ब्रैंड्स के तमाम संचालको ने व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में गुरुवार को मुलाकात की । मीटिंग को लेकर CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट्स एवं फूड व्यापारियों को जीएसटी को लेकर बहुत सारी परेशानी आ रही है इसी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की क्योंकि उनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार हैं , वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए फूड इंडस्ट्री की समस्या ऊपर तक

पहुंचाएंगी। रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, वहीं खाने के बाद आइसक्रीम खाई, तो 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। रोटी पर 5 प्रतिशत, तो पराठे पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। कोई गेस्ट एक रोटी और दो परांठे खा ले, तो बिल बनाने में परेशानी होती है। रेस्टोरेंट में एसी चल रहा हो या नहीं चल रहा हो लेकिन यदि जीएसटी में एसी रजिस्टर्ड है, तो हर फूड आइटम पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा। ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगता है मगर पिज्जा बेस पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। लस्सी गिलास में ली तो जीरो टैक्स वहीं पैकेट में ली, तो 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। यदि प्लेन काजू लिया तो 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा लेकिन उस पर नमक या मसाला लग गया, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।पाउडर फोम में चटनी लेंगे, तो 5 प्रतिशत और लिक्विड फोम में लेंगे, तो 12 प्रतिशत जीएसटी है। खुली नमकीन पर 5 प्रतिशत और पैक्ड नमकीन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है।इस तरह कई दिक्कत बिलिंग में व्यापारी और कस्टमर को होती है। फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के प्रेजिडेंट ने वीरेंद्र जैन ने कहा कि अब रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री चलाने में मुश्किल आ रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी होती है। सरकारी अधिकारी आते हैं, तो गैर जरूरी कागज मांगते हैं। उन्हें समझाना आसान नहीं होता है। विसंगतियों के बीच जीएसटी के नॉर्म्स पूरा करना ईमानदार व्यापारी के लिए मुश्किल हो गया है। कितना सामान खुला और कितना पैक्ड बेचा, इसका ब्यौरा रखना मुश्किल काम है। सॉफ्टवेयर तक फेल हो गए।एक गिफ्ट हेंपर में पांच तरह के जीएसटी स्लैब लग रहे हैं। नमकीन, मिठाई, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक पर अलग जीएसटी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह विषय उठाने का भरोसा दिया है, इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के जीएसटी अधिकारियों को भी इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है मीटिंग में फूड सेक्टर के व्यापारियों ने बताया कि दिल्ली में डबल लाइसेंस सिस्टम फूड इंडस्ट्री झेल रही है। FSSAI से हेल्थ लाइसेंस लेने के बावजूद एमसीडी अलग से हेल्थ लाइसेंस थोप रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। देश में ऐसा कहीं नहीं है। मीटिंग में प्रियंका सक्सेना, संजय सिंघानिया, किशन अग्रवाल, आनंद गुप्ता, विनय अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल और नवीन गुप्ता मौजूद रहे।

अभिनेत्री कशिका कपूर और अभिने२त्री उल्का गुप्ता ने निकाला इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के 50 लाख रुपये के पुरस्कारों

दिव्य दिल्ली : ग्राहकों के साथ अटूट रिश्ते और संतुष्टि की विरासत के लिए जाने जाने वाले देश के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ने 9 जुलाई को 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार बांटे। इसके लिए राजौरी गार्डन स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के विशाल स्टोर पर पुरस्कार के समर सीजन स्पेशल ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस गर्मी के मौसम में समर ड्रॉ ऑफर के तहत 50 लाख रुपये के पुरस्कार के लिए अभिनेत्री कशिका कपूर और अभिनेत्री उल्का गुप्ता ने लकी विजेताओं के कूपन निकाले। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ये अपनी तरह का अनूठा ऑफर है।इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की 100 फीसद ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने की गहरी रुचि और प्रयास के तहत इस तरह के आयोजन ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों का दिल जीत

लिया है 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार के तहत 5 विजेताओं को 10-10 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। इस लक्की ड्रा में कूपन संख्या झ 25097172, 25256966, 25217496, 25005373, और 25244259 ने 10-10 लाख रुपये जीते।इस अवसर पर अभिनेत्री कशिका कपूर और उल्का गुप्ता ने 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं दीं और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में खरीदारी करते रहने और रोमांचक पुरस्कार जीतते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उल्लेखनीय है कि भारत के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर - बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 200 से अधिक मेगा स्टोर हैं।इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट स्टोर एलईडी टीवी, घरेलू और रसोई के उपकरणों, मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स, एक्सेसरीज आदि की विस्तृत श्रृंखला के साथ आसा२न ईएमआई विकल्पों के साथ बेस्ट प्राइस पर खरीद का अद्भुत अनुभव देता है।इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट के सीईओ करण बजाज ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपने लॉन्च के बहुत ही कम समय में यह सफलता हासिल की है।" उन्होंने आगे कहा, "बम्पर ड्रॉ एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में अपने ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हम कामना करते हैं कि ग्राहकों के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा हो।"

हम 50 लाख रुपये के नकद पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देते हैं।ज्ञातव्य है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, गैजेट्स और भी बहुत कुछ खरीदने के विकल्प हैं। असाधारण ऑफर, मनमोहक डील्स, आसान ईएमआई विकल्प इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं।

संदिग्ध अवस्था में महिला का शव घर के अंदर मिला

बिंदकी, फतेहपुर। संदिग्ध अवस्था में महिला का शव घर के अंदर मिला। मामले की जानकारी होने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस के अनुसार मामला फांसी लगाकर आत्महत्या करने का लगता है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि मायका पक्ष के लोग मामले को कुछ अलग बता रहे हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के जनता गांव में शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बजे घर के अंदर साजमा उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी इजरायल का शव संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर मिला तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग भी पहुंचे। मृतक महिला के पिता रईस निवासी मोहल्ला सुनराही गली कस्बा जहानाबाद थाना जहानाबाद ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री के साथ पति तथा ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने मारपीट की जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बिंदकी लान सिंह ने बताया कि महिला की मौत हुई है। महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात आ रही है। लेकिन मृतक महिला के मायके पक्ष के लोगों का कुछ दूसरा आरोप है। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण का समापन, शैक्षिक गुणवत्ता पर रहा जोर

फतेहपुर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आयोजित पांच दिवसीय ब्लॉक स्तरीय संदर्भदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को उत्साहपूर्ण संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण सत्र अकादमिक सत्र 2025-26 के तहत एफएलएन व एनसीईआरटी आधारित नवीन पाठ्यपुस्तकों पर केंद्रित रहा। जिसका उद्देश्य शिक्षकों की विषयगत समझ और शैक्षिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक संजय कुशवाहा एवं वरिष्ठ प्रवक्ता आरती गुप्ता, प्रशिक्षण प्रभारी विनय कुमार मिश्र और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के निर्देशन में किया गया। प्रशिक्षण में नगर क्षेत्र सहित 13 विकास खंडों से आए एआरपी एवं केआरपी प्रतिभागियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज की। मुख्य संदर्भदाता डायट मेंटर संजीव सिंह, शाइस्ता इकबाल, एसआरजी सदस्य राजेश त्रिपाठी, राधेश्याम दीक्षित और जयचंद्र पांडेय ने प्रशिक्षण सत्रों में मार्गदर्शन किया। समापन सत्र में प्रशिक्षण प्रभारी विनय मिश्र ने पांच दिनों की समेकित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण की सुचारू रूप से जानकारी दी।

पौधरोपण व शिवपूजन कर दिया पर्यावरण और भक्ति का संदेश

फतेहपुर। युवा विकास समिति द्वारा मवई ग्राम के वृद्धा आश्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में 20 पौधों का वृक्षारोपण कर हरियाली और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल ऑक्सीजन का स्रोत नहीं, जीवन की छांव भी हैं, जिनके बिना भविष्य की कल्पना अधूरी है। इसके बाद सावन के पहले दिन वृद्धजनों के बीच शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्रोच्चार के साथ शिव पूजन का आयोजन किया गया। धूप, दीप, चंदन, फूल और

फल के साथ भक्तिभाव से पूजा की गई। नमः शिवाय की गूंज से वृद्धाश्रम का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। पूजा के समापन पर आरती हुई और सभी को प्रसाद वितरण किया गया। ज्ञानेंद्र मिश्रा ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे जहां भी संभव हो, पौधारोपण करें और हरीतिमा को बढ़ाने में सहयोग दें। उन्होंने बिगड़ते पर्यावरण पर चिंता जताते हुए हर नागरिक से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

इस विशेष अवसर पर संगठन प्रमुख

दुर्भाग्यपूर्ण घटना: करंट लगने से किशोर की मौत

शाहजहांपुर। खुदागंज के ग्राम पंचायत जलालपुर में एक दर्दनाक घटना घटी, जहां 20 वर्षीय किशोर गोपाल पांडे उर्फ सोनू की करंट लगने से मौत हो गई। वह सुबह लगभग 5:00 बजे नल पर किसी कार्य से गए थे, जब उनका पैर संभवतः मोटर से टच हो गया और मोटर में करंट आने के कारण यह दुर्घटना हुई। गोपाल पांडे उर्फ सोनू की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। वह दो भाई थे और इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते थे। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस घटना की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुरक्षा को लेकर जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता है ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके।

श्रवण मास में शिव पूजन से कटती है जीवन की बाधाएः आयुष द्विवेदी

श्रवण मास में विशेष करनी चाहिए शिव आराधना

फतेहपुर। जहां एक ओर शुक्रवार से श्रवण मास का प्रारंभ हुआ तो वही दूसरी ओर लोग शिव आराधना में लग गए। श्रवण मास के आते ही शिव मन्दिरो में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग घरों में शिव रूद्राभिषेक करवाकर महादेव की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। मां पन्थेश्वरी देवी धाम खजुहा के प्रमुख पुजारी आयुष द्विवेदी ने बताया कि श्रवण मास में शिव रूद्राभिषेक करने से महादेव की भक्तों पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। वेदों के अनुसार साक्षात शिव ही वेद स्वरूप परम ब्रम्ह है। श्रवण मास विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस मास के

अन्तर्गत प्रत्येक सामर्थ्यवान मनुष्य को भगवान शिव की आराधना एवं रूद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। श्रवण मास में रुद्राभिषेक से मनुष्य को धन, सुख, सम्पत्ति, रोगों से निजात, कीर्ति व नव ग्रह जनित पीड़ा से शान्ति मिलती है।

बर्तन व्यापारी की सड़क दुर्घटना में मौत, पांच लोग घायल

बिंदकी, फतेहपुर। बिंदकी के रहने वाले बर्तन व्यापारी की उन्नाव जनपद में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि उसी चार पहिया वाहन में सवार पांच लोग घायल भी होगए। चार पहिया में सवार सभी लोग उन्नाव जनपद के बीघापुर रिश्तेदारी में एक नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस अपने घर बिंदकी आ रहे थे। मृतक का शव घर आने पर परिजनों में हड़कंप मच गया परिजन रो-रो कर बेहाल हो रहे थे सभी लोग दुर्घटना में दुख जाता रहे थे। जानकारी के अनुसार कोतवाली बिंदकी कस्बे के मोहल्ला पैगंबर पुर निवासी सुनील गुप्ता उम्र लगभग 44 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल गुप्ता कई लोगों के साथ गुरुवार को अपने रिश्तेदारी में उन्नाव जनपद के बीघापुर कस्बा गृह प्रवेश कार्यक्रम में चार पहिया द्वारा गए थे। गुरुवार की देर रात को कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सभी लोग चार पहिया वाहन से वापस आ रहे थे। तभी उन्नाव जनपद के बारा सगवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवरतनपुर गांव के समीप तेज रफ्तार से जा रहे अनियंत्रित ट्रक ने चार पहिया वाहन में टक्कर मार दी। जिसके चलते चार पहिया वाहन में सवार सुनील गुप्ता उम्र 44 वर्ष पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल, राधा देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी गोरे, गोरे उम्र 40 वर्ष, पूनम देवी उम्र 35 वर्ष पत्नी सुनील, नेहा उम्र 10 वर्ष पुत्री गोरे तथा चालक दीपक सभी निवासी कस्बा बिंदकी कोतवाली बिंदकी जनपद फतेहपुर घायल हो गए। जिसमें गंभीर घायल सुनील गुप्ता को दुर्घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीघापुर जनपद उन्नाव में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया। जिला अस्पताल उन्नाव ले जाते समय सुनील गुप्ता की रास्ते में मौत हो गई।

कांवर सेवा शिविरों से कर्मचारी नदारद

हाथरस। जलेसर मार्ग पर कांवड़ियों के लिए बनाए गए विश्राम टेंट में कर्मचारियों की अनुपस्थिति का मामला सामने आया है। सुबह 8:30 से 9:00 बजे के बीच टेंट में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। कांवड़ियों को मेडिकल सहायता और विश्राम की सुविधा देने के लिए बनाए गए इन टेंट की स्थिति सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक स्थान पर सफाई व्यवस्था भी उचित नहीं थी, जहां कर्मचारी केवल घास काटने में व्यस्त थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. प्रकाश मोहन ने कहा कि अनुपस्थित सीएचओ के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाएगी।

किशोर 24 घंटे से लापता, पुलिस जांच में जुटी

बिंदकी, फतेहपुर। कक्षा 8 में पढ़ने वाला 14 वर्षीय किशोर 24 घंटे से अधिक समय से लापता है परिजनो ने काफी खोजबीन किया लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चल पा रहा है। पिता ने मामले की सूचना पुलिस को दी है पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिंदकी कस्बे के मोहल्ला पुरानी बिंदकी मां ज्वाला देवी मंदिर के पास के निवासी राजकुमार गुप्ता का 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस गुप्ता उर्फ देवेंद्र गुप्ता उम्र लगभग 14 वर्ष गुरुवार की देर शाम लगभग 6:30 बजे अचानक मोहल्ले से लापता हो गया। जिसका शुक्रवार को दिन में 6:30 बजे तक यानी लगभग 24 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चला। इस मामले में लापता किशोर के पिता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि काफी खोजबीन की गई है लेकिन पुत्र का कोई पता नहीं चल पा रहा है उन्होंने बताया कि उनका पुत्र बिंदकी कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 8 का छात्र है। बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है।

बनपुरवा में पत्नी से नाराज होटल कर्मी ने लगाया फांसी, मौत

असोथर, फतेहपुर। नगर पंचायत असोथर के बनपुरवा वार्ड निवासी शिवभवन उम्र करीब 30 वर्ष गांव के बाहर बांस के पेड़ में गमछे से फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया है मृतक दो दिन पहले मुंबई से लौटा था मुंबई की एक होटल में हलवाई गीरी का काम करता था मृतक की शादी साढ़े तीन साल पहले हुई थी पत्नी संगीता अपने पुत्र शिवांश उम्र करीब एक वर्ष पुत्री दिव्यांशी उम्र करीब ढाई वर्ष के साथ मायके इंगुवा मऊ जिला बांदा में थी 15 दिन पहले होटल कर्मी मुंबई गया था और तीन दिन पहले लौट कर घर आया तो पत्नी मायके में थी इसके पहले जब पत्नी मायके गयी थी तो दूसरे दिन शिवभवन भी अपनी ससुराल गया था अनुमान है कि वहीं पति-पत्नी के बीच कहा सुनी हुई होगी इसके बाद शिवभवन मुंबई चला गया और मुंबई से जब लौट कर आया तो पत्नी घर नहीं आई शिवभवन गुमसुम रहता था और दोस्तों से कहा था कि अब मुझे मरना है दिन में करीब 12 बजे गांव के बाहर अपने कुछ कागजात फाड़ के फेंक दिया और वहीं पर बांस की डाल पर गमछा से गला कस कर लटक गया ।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है मृतक सगे चार भाई सोमनाथ,ननका, रतीलाल है और तीन बहने फूलमती शकुंतला प्रीति है तीनों की शादी हो गई है पिता भूराप्रसाद माता संपत्तिया का रो-रो कर हाल बेहाल है घटना की जानकारी तब हुई

जब छोटे बच्चे जामुन तोड़ने बाग में गए थे।

'जवानी घट नहीं रही और बुढ़ापा...'

श्वेता तिवारी

का डांस देख सोच में पड़ गए लोग, बोले- क्या खाती हो?

44 साल की श्वेता तिवारी ने इंटरनेट पर अपनी फिटनेस और खूबसूरती के जरिए हलचल मचा रखी है. हर कोई उनके ग्लैमर का दीवाना हो गया है. दो-दो बच्चों की मां होने के बावजूद उम्र का श्वेता पर कोई असर नहीं हो रहा है. हर गुजरते दिन के साथ एक्ट्रेस जवान होती जा रही हैं. जब भी श्वेता कोई फोटो शेयर करती हैं, लोग उनकी फिटनेस के कायल हो जाते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर श्वेता का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं लोगों का ध्यान उनके डांस पर कम और उनकी उम्र का हिसाब लगाने में ज्यादा नजर आ रहा है.

श्वेता तिवारी अपने बेटे और बेटी पलक के साथ छुट्टियां मना रही हैं. वो आए दिन अपने वेकेशन से तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर रही हैं.

वहीं इसी बीच श्वेता का नया वीडियो काफी चर्चा में हैं. एक्ट्रेस को डांस करते हुए कम ही देखा जाता है. लेकिन अपनी जिंदगी को फिलहाल अपने बच्चों के साथ एक्ट्रेस खुलकर जी रही हैं. कसौटी जिंदगी की की प्रेरणा ने असल जिंदगी में काफी बुरा दौर देखा है. उन्होंने निजी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव का सामना किया है.

बादशाह के गाने पर थिरकीं श्वेता तिवारी

चलिए बात करते हैं श्वेता तिवारी के वायरल हो रहे वीडियो की. क्लिप में ब्लैक कलर की स्पेगेटी टॉप और डेनिम जींस के साथ श्वेता ने अपनी कमर में जैकेट बांधी हुई हैं. हाई हील्स, खुले बाल और कानों में लंबे-लंबे इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पूरा किया है. इस वीडियो में श्वेता बेहद हसीन लग रही हैं, उन्हें देखकर ये कहना कि वो 44 साल की है ये गलत होगा. एक्ट्रेस रैपर बादशाह के गाने 'सब गजब' पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं.

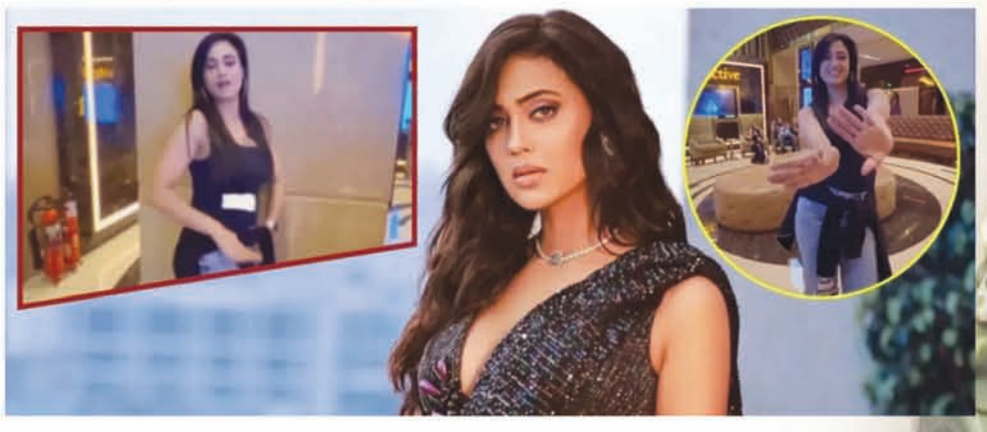

श्वेता का डांस देख फैन्स बोले घट नहीं रही...

श्वेता तिवारी का मस्ती भरा अंदाज देख सोशल मीडिया यूजर्स खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं. कुछ एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ बस उनकी उम्र पर गौर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इन्हें देखते-देखते हम बच्चे से बूढ़े हो जाएंगे और ये वैसी ही रहेंगी. एक दूसरे यूजर ने लिखा, बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत. अन्य यूजर ने लिखा, जवानी घट नहीं रही और बुढ़ापा आ नहीं रहा.

श्वेता से फैन्स ने पूछा- आप बड़ी कब होंगी ?

इतना ही नहीं यूजर्स ने अपने-अपने अंदाज में श्वेता की तारीफ करने का सिलसिला जारी रखा. यूजर ने लिखा, मैम आप बड़ी कब होंगी ? आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं, जैसे कसौटी के दौरान थीं. एक यूजर ने तो श्वेता की डाइट ही पूछ ली. उन्होंने लिखा, ये क्या खाती हैं भाई..इनका डाइट चुरा लोज्इनकी बेटी जवान हो रही है और ये अपनी बेटी से भी ज्यादा यंग लग रही हैं.

पायल रोहतगी के फाउंडेशन छोड़ने पर संग्राम सिंह का दो टूक जवाब, तलाक पर भी तोड़ी चुप्पी

टीवी की दुनिया के पावर कपल संग्राम सिंह और पायल रोहतगी अपनी शादी की तीसरी सालगिरह मना रहे हैं. इस खास मौके पर जहां एक तरफ ये कपल एक-दूसरे के साथ यादगार पल बिता रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उड़ी तलाक की अफवाहों पर संग्राम सिंह ने खुद चुप्पी तोड़ी है. दरअसल पायल रोहतगी के एक खास पद से इस्तीफा देने के बाद ये खबरें तेज हुई थीं, जिस पर अब संग्राम ने दो टूक जवाब देकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.हाल ही में पायल रोहतगी ने 'संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन' में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था. पायल के इस सोशल मीडिया पोस्ट के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल पूछने लगे कि क्या पायल और संग्राम के रिश्ते में दरार आ गई है ? क्या दोनों अब तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं ? ये खबर इतनी वायरल हुई कि आखिरकार संग्राम को सामने आकर इस बारे में बात करनी पड़ी.

संग्राम सिंह ने तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

संग्राम सिंह ने साफ शब्दों में कहा,हमारे बीच में तलाक की कोई बात दूर-दूर तक भी नहीं है. हम पिछले 14 साल से साथ में रह रहे हैं और हमेशा साथ में रहेंगे. मैं हमेशा अपना पूराध्यान अच्छे काम करने में लगाता हूं. इस तरह की तलाक की बातों पर मैं कभी भी ध्यान नहीं देता और मैं बाकी सभी से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो कृपा करके इस तरह की कोई अफवाह न फैलाएं.

पायल के फैसले का सम्मान करते हैं संग्राम

पायल रोहतगी के 'संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन' से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने की बात पर भी संग्राम ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से पायल जी का फैसला है और मैं उनके इस फैसले का दिल से सम्मान करता हूं. हम दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं. इसलिए शायद पायल जी इस तरह का कोई फैसला लिया होगा और वो अपने हिसाब से बेहतर ही होगा. काम के मामले में मैं किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं करता. वो अपने फैसले खुद लेती हैं. यहां कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है.

सुनीता संभालेंगी चैरिटेबल फाउंडेशन का काम

पायल रोहतगी की जगह अब संग्राम सिंह की बड़ी बहन सुनीता कुमारी सिंह उनके फाउंडेशन की नई डायरेक्टर होंगी. वो अपने भाई संग्राम सिंह के साथ मिलकर इस फाउंडेशन का काम संभालेंगी. संग्राम सिंह चाहते हैं कि उनके इस फाउंडेशन को वो एक मुकाम तक ले जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और बेसहारा बच्चों को मदद और शिक्षा मिल सके.

मरने और लड़ने में एक चुनना हो... आ गई 'Dhadak 2' की रिलीज डेट, इस दिन आएगा तृप्ति-सिद्धांत की फिल्म का ट्रेलर

बॉलीवुड में हमेशा से ही प्रेम कहानियों का चलन रहा है. लव स्टोरीज को फैंस का हमेशा ही प्यार मिला है. अब अलग तरह की स्टोरी का दौर भले आ गया हो जहां मसाला और थ्रिलर फिल्मों का क्रेज लोगों में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बेहतरीन लव स्टोरीज के लिए फैंस हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं. एक ऐसी ही फिल्म है धड़क, जिसका दूसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है.

साल 2018 में आई फिल्म धड़क एक बहुत की हार्ड हिटिंग फिल्म थी. इस फिल्म से हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की बेटी जान्हवी कपूर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. साथ ही जान्हवी के ऑपोजिट शाहिद कपूर के भाई और एक्टर ईशान खट्टर ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. फिल्म में दोनों की केमेस्ट्री और एक्टिंग की सभी ने काफी तारीफ की थी.

इस दिन आएगा धड़क 2 का ट्रेलर

'धड़क' मराठी सुपरहिट फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक थी. अब मेकर्स धड़क का दूसरा पार्ट यानी धड़क 2 लेकर आ रहे हैं. फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी और एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आने वाले हैं. ये पेयरिंग काफी फ्रेश है. अब फैंस को जल्द ही फिल्म की झलक देखने को मिलेगी क्योंकि आने वाले फ्राइडे यानी 11 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. फिल्म का फैंस को काफी लंबे वक्त से इंतजार है. इसके साथ ही मेकर्स ने रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है.

कब रिलीज होगी फिल्म ?

फिल्म के लीड कपल तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट को शेयर किया है. ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म मेकर्स ने पोस्टर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है 'दो दिल एक धड़क'. इसका निर्देशन नागराज मंजुले ने किया था. हाल ही में 16 कट के बाद 'धड़क 2' को यूए सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म में गालियों को म्यूट किया गया है और 'सवर्ण' शब्द के इस्तेमाल को हटा दिया गया है. फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

जरीन खान

के घर में गूंजी किलकारी, नन्हीं परी ने लिया जन्म, खुशी से झूम उठीं एक्ट्रेस

एक्ट्रेस जरीन खान के घर में खुशियों ने दस्तक दी है. उनके घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया है. उनकी बहन सना ने बेटी को जन्म दिया है. जरीन खान आंटी बन गई हैं. जरीन ने खुद इसकी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने दो प्यारी तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. अब फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

एक फोटो में जरीन बच्ची का हाथ पकड़ी नजर आ रही हैं. वहीं दूसरी फोटो में उन्होंने बच्ची को गोद में ले रखा है. जरीन ने बच्ची का चेहरा नहीं दिखाया है. उन्होंने चेहरे को हार्ट इमोजी से ढक दिया है. एक्ट्रेस ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पहली नजर वाला प्यार होता है. वेलकम मेरी नन्ही भांजी- आईजल खान.

बच्ची के साथ इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेट

तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस हर तरफ से उन्हें आंटी बनने की बधाई दे रहे हैं. आईजल खान के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर क्रिएट किया गया है. जरीन ने फोटोज शेयर करते हुए बच्ची के इंस्टाग्राम को कोलैबोरेट भी किया है.

बेबी गर्ल के इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है, मैं आईजल खान हू. प्यार से बिगड़ी हूं. दूध से ताकत मिलती है. मैं क्यूटी हूं. मां सना खान, जरीन खान और नानी मेरी सबसे बड़ी फैन हैं. जरीन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

जरीना खान की आखिरी फिल्म

जरीन अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखती हैं और इंस्टाग्राम पर फिटनेस से जुड़े वीडियोज भी पोस्ट करती हैं. लंबे समय से वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हैं. वो सोशल मीडिया के जरिए ही फैंस के साथ कनेक्ट रहती हैं. जरीना आखिरी बार साल 2019 में आई फिल्म 'हम भी अकेले तुम भी अकेले' में दिखी थीं. उसके बाद उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोज भी किए हैं.

बहरहाल, जरीन ने साल 2010 में आई सलमान खान की फिल्म 'वीर' से डेब्यू किया था. इस फिल्म का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और एवरेज रही थी. हालांकि, जरीन को इससे काफी पॉपुलैरिटी मिली थी.

न्यूज फ्लैश

3.5 किलो चूरा पोस्त सहित 2 बस यात्री काबू

दिव्या दिल्ली-कंवल रंधावा (पठानकोट)

पंजाब पुलिस ने माधोपुर नाके के दौरान एक बस में सवार दो यात्रियों से साढ़े तीन किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ मोहित टाक ने बताया कि एएसआई बलजीत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ माधोपुर में नाका लगाया हुआ था। जम्मू-कश्मीर से आ रही हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक बस को रोककर तलाशी ली गई तो दो यात्रियों से साढ़े तीन किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। आरोपियों की पहचान जसवीर सिंह उर्फ बीरू निवासी अखाड़ा, थाना फगवाड़ा, जिला जालंधर और अजीत कुमार उर्फ अमरजीत निवासी गांव न्योली, थाना फगवाड़ा, जिला जालंधर के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ सुजानपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और आगे की जांच जारी है।

जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उपायुक्त किरण भड़ाना ने किया त्रिलोकीनाथ मंदिर का दौरा

दिव्या दिल्ली- रणजीत लाहुली (लाहौल)

स्पीति की उपायुक्त एवं विश्व विख्यात त्रिलोकीनाथ मंदिर की आयुक्त किरण भड़ाना (भा.प्र.से) ने शुक्रवार को त्रिलोकीनाथ मंदिर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। दौरे के दौरान उपायुक्त किरण भड़ाना ने मंदिर परिसर में प्रस्तावित सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने उपमंडलाधिकारी उदयपुर एवं मंदिर अध्यक्ष अलीशा चौहान, सहायक अभियंता (यांत्रिक) लोक निर्माण विभाग राजेन्द्र, कनिष्ठ अभियंता गिरधारी लाल, मंदिर सहायक जय सिंह ठाकुर समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मंदिर के सौंदर्यीकरण, विस्तार एवं निर्माण कार्यों की योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मंदिर सौंदर्यीकरण हेतु तैयार किए गए प्राक्कलन व ड्राइंग की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप व लौहली भवन शैली में ही किए जाएं, ताकि मंदिर की मूल सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।

विकास खंड कार्यालय स्थानांतरित होने पर जवाली के प्रधानों ब बुद्धिजीवियों ने कृषि मंत्री का किया धन्यवाद

दिव्या दिल्ली- ऊषा (जवाली)

मिनी सचिवालय जबाली में विकासखंड आने से साथ लगती पंचायत के लोगों को पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि फतेहपुर के साथ लगती पंचायत को 40 किलोमीटर दूर नगरोटा सूरिया जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था

उपमंडल जवाली के अंतर्गत लोक निर्माण बिभाग के जवाली में विश्राम गृह जवाली में समस्त पंचायत प्रधानों व जनता ने राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मनमोहन सिंह व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह की अध्यक्षता में विश्रामगृह जवाली में बैठक की। मनमोहन सिंह व चैन सिंह ने कहा कि विकासखंड कार्यालय नगरोटा सूरियां को मिनी सचिवालय जावली में स्थानांतरित होने पर जवाली कस्बे के सभी पंचायत के प्रधानो तथा फतेहपुर विकासखंड की 14 पंचायतो जो जवाली के साथ जोड़ी गई है के प्रधानों ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का आभार प्रकट किया हैं उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय जबाली में विकासखंड आने से साथ लगती पंचायत के लोगों को पूरा लाभ मिलेगा क्योंकि फतेहपुर के साथ लगती पंचायत को 40 किलोमीटर दूर नगरोटा सूरिया जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा थो जिससे एक काम के लिए पूरा दिन नगरोटा सुरियाँ में ही लग जाता था जिसके लिए फतेहपुर के साथ कुछ पंचायतें जो जवाली बिकास खंड के साथ जोड़ी गई है तथा जवाली के साथ लगती पंचायत के प्रधानों ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री का उनकी समस्या का हल करके बहुत ही खुशी हुई है।

नेशनल मेडिकल फोरम और दिल्ली के सभी अस्पतालों की मांग जबरन थोपी जा रही एसटीपी प्रणाली को समाप्त किया जाए

दिव्य दिल्ली : नेशनल मेडिकल फोरम और दिल्ली हॉस्पिटल फोरम के अध्यक्ष, संजीवन अस्पताल के चेयरमैन डॉ. प्रेम अग्रवाल ने राजधानी के अस्पतालों पर जबरन थोपे जा रहे अव्यवस्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी सिस्टम को लागू करने के सरकारी दबाव पर कड़ा विरोध प्रकट किया है ।डॉक्टर अग्रवाल ने कहा यह प्रणाली पूरी तरह से गैर-जरूरी है, अगर इस प्रणाली को लागू किया जाता है तो अस्पताल प्रबंधन के अलावा डॉक्टरों और स्टाफ कर्मियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है। उन्होंने बताया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा 2016 में लागू की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली के निजी अस्पतालों में लागू केन्द्रीय एसटीपी सिस्टम सुरक्षित और पर्याप्त हैं, इससे ट्रीटमेंट के बाद अस्पतालों का जल रिसायकल होता है और यह सिस्टम पूरी तरह से सभी सुरक्षा नियमो पर भी खरा उतर सका है लेकिन ना जाने क्यों दिल्ली के सभी अस्पतालों को अपने-अपने यहां एसटीपी लगाने को मजबूर किया जा रहा है।

यह प्रक्रिया कही भी सफल नहीं रही ,बल्कि इससे अस्पताल प्रशासन पर अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी बोझ पड़ने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।फोरम के सभी सदस्यों के साथ अध्यक्ष डॉ. प्रेम अग्रवाल ने इस संबंध में उपराज्यपाल विनय सक्सेना महोदय से शीघ्र हस्तक्षेप करने के की मांग करते हुए कहा है प्रशासन उन अस्पतालों को एसटीपी लगवाने को बाध्य न करे जो पहले से ही केन्द्रीय सीवेज प्रणाली से जुड़े हुए हैं दिल्ली की सीवेज प्रणाली में सुधार करके अधिक मजबूत किया जाए जिससे दिल्ली के अस्पतालो पर बेवजह वित्तीय और तकनीकी दबाव न पड़े ।

पूर्व मंत्री राकेश पठानिया कुछ होटलों को लीज पर देने पर सरकार पर खुलकर बरसे

दिव्या दिल्ली- विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया ने पिछले दिनों कैबिनेट में हुए एच पी टी डी सी के कुछ होटलों को रिलीज पर देने के निर्णय के मामले में सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री की कारगुजारी पर कई प्रश्न उठाएं ' हिमाचल प्रदेश के पूर्व वन मंत्री को भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश पठानिया ने आज नूरपुर मे अपने गृह निवास पर एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू की सरकार पर एच पी टी डी सी के कुछ होटलों को रिलीज पर देने के मुद्दे पर कहा कि सरकार की नीयत और नजर दोनों इस मामले मे ठीक नहीं है' आज प्रदेश में जनता मौजूदा सरकार से दुखी है और एचपी टीडीसी में कर्मचारियों की संख्या काफी घट गई है उन्होंने सरकार की नीति और नीयत पर एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार की करगुजारी पर अनिल को सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सिर्फ 2 साल का इंतजार कर रही है' इस समय प्रदेश आपदाओं से घिरा हुआ है ' उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐसा निर्णय ले जाना हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा मजाक तो है लेकिन एचडीसी के कर्मचारियों के साथ भी बड़ा मजाक है ' उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा मौजूदा सरकार के एक कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे जबकि उनके क्षेत्र का होटल भी लीज पर देने का निर्णय लिया गया है और वह चुप रहे ' उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस इस निर्णय को नहीं बदलता तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ ऐसी नीतियों को लेकर जनता में करेगी।

शाहपुर कंडी में विस्थापित परिवार अपने रोजगार की मांग को लेकर 101वें दिन भी विशाल रोष प्रदर्शन किया

दिव्या दिल्ली-कंवल रंधावा (पठानकोट)

शाहपुर कंडी बैराज बांध विस्थापित परिवारों ने अपने रोजगार की मांग को लेकर 101वें दिन भी अपनी भूख हड़ताल व रोष प्रदर्शन जारी रखा। यह रोष प्रदर्शन व भूख हड़ताल बैराज बांध औसती कमेटी शाहपुर कंडी के पदाधिकारी कामरेड जसवंत संधू की देखरेख में , डैमेज प्रशासन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर चल रहा है, जिसमें आज 101वें दिन पर विकास कुमार शाहपुर कंडी, सतीश कुमार अवां, अजय कुमार छन्नी मोआला, सन्नी कोट व दर्शन सिंह जैनी ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। रोष प्रदर्शन कर रहे विस्थापित परिवारों में से जिनमें कामरेड जसवंत संधू, सुरजीत सिंह, रविंद्र बाबा, रोहित कुमार , अंशु शर्मा, रमेश कुमार, हनी कुमार, कुलदीप शर्मा, रजत बालोतरा, जसविंदर सिंह, आदर्श वाला, शक्ति देवी, सुनीता देवी, विनोद कुमारी, बीतू देवी, कमलेश कौर, यशोदरा देवी, राहुल शर्मा, शाम लाल, धर्मपाल , कर्णवीर सिंह , जनक राज, रविंद्र शर्मा व अन्य कई प्रभावित परिवार शामिल हुए। विस्थापित परिवारों ने कहा कि , बैराज बांध अधिकारियों ने जानबूझ कर पुरानी पालिसी पर ऐतराज लगा कर उचित परिवारों को रोजगार से वंचित करने की साजिश रची है, जो उनकी सहनशीलता से बाहर है। कमेटी ने बताया कि यदि उनके प्रभावित हुए परिवारों के लिए रोजगार देने के लिए शीघ्र ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह 15 जुलाई को फिर से चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर विशाल रोष प्रदर्शन करेंगें।

मंडी जिला में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 180 बिस्तर सम्मान पूर्वक रवाना

दिव्या दिल्ली-अमरप्रीत सिंह (सोलन)

सोलन के समाजसेवी व व्यापारियों ने मंडी जिला में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 180 पूर्ण बिस्तर सम्मान पूर्वक रवाना किए और आपदा में जिन लोगों की जान गई हैं उनके सभी योगदान करने वालों की और से श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रभावितों के शीघ्र पुनर्वास के लिए प्राथना करते हुए संवेदनाएं प्रकट की समाजसेवी व व्यापार मंडल सोलन के पूर्व प्रधान मुकेश गुप्ता ,सचिव मनोज गुप्ता,वैश्य समाज के अध्यक्ष रमेश बंसल (राजा भाई),पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत, राकेश अग्रवाल, अंजुल अग्रवाल,दिनेश कश्यप, आशीष विशेष रूप से मौजूद रहे। मुकेश गुप्ता ने कहा कि भेजा गया समान इस आपदा की घड़ी में सुदामा के चावल की तरह है पर इस समय फौरी राहत के लिए आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए योगदान करना हर हिमाचल वासी का कर्तव्य हैं प्रभावित परिवारों हमारे ही भाई,बहन, बुजुर्ग और बच्चे हैं। हमें आशा है हमारे प्रभावित परिवारों के सदस्य इस योगदान को स्वीकार करेंगे।

साईं संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल कार्यक्रम आयोजित

दिव्या दिल्ली- अमरप्रीत सिंह (सोलन)

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर साईं संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, सोलन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम अवसरों का सशक्तिकरणः प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का भविष्य रखा गया. कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन डॉ. संजय अग्रवाल एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. सविता अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया एवं जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता पर आधारित रचनात्मक प्रस्तुतियां दीं। रंगोली प्रतियोगिता इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रही। छात्राओं ने जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संतुलन एवं स्वास्थ्य के महत्व को रंगों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

पुलिस ने 12 बोतल अवैध शराब सहित एक व्यक्ति को पकड़ा

दिव्या दिल्ली-कंवल रंधावा (पठानकोट)

जिला पुलिस प्रमुख डीएस ढिल्लों की हिदायत अनुसार, नशे पर नकेल कसने के लिए शाहपुर कंडी पुलिस ने छापामारी करके, एक व्यक्ति से 12 बोतल अवैध शराब बरामद की है। शाहपुर कंडी पुलिस स्टेशन की एसएचओ सब इंस्पेक्टर अमनप्रीत कौर अनुसार, गत देर सांयकाल उनकी पुलिस की ओर से वाहनों की चेकिंग के लिए पंगोली चौक के समीप नाका लगाया हुया था तथा उस समय उनको किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि, एक व्यक्ति अपनी कार में अवैध शराब ला कर गांव में बेचने का कार्य करता है।

रणजीत सागर डैम पावर हाउस में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों ने किया देश व्यापी हड़ताल का समर्थन

दिव्य दिल्ली : रंधावा (पठानकोट)

रणजीत सागर डैम में कार्यरत कंट्रेक्चुअल वर्कर्ज यूनियन, पंजाब ने देश की समूह ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की जा रही देश व्यापी हड़ताल के समर्थन में पावर हाउस में रोष रैली करके केंद्र तथा प्रदेश सरकार की लोक विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। इस मौके पर जानकारी देते हुए यूनियन के प्रदेश महासचिव हरजीत सिंह टड़वाल ने कहा कि इस देश व्यापी हड़ताल का उद्देश्य केंद्र की "मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी, कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों" के खिलाफ विरोध करना है। केंद्र तथा पंजाब सरकार मजदूरों के हितों के विपरीत निर्णय लेना जारी रखे हुए है", तथा मजदूरों के पक्ष में बने 48 लेबर कानूनों को तोड़कर चार नए लेबर कोड में तब्दील कर दिया है । केंद सरकार लगातार सरकारी विभागों और सेवाओं के निजीकरण करके देश के सभी संसाधन चन्द घरानों को सुपुर्द कर रही है। सरकार ने सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे, कारखाने आदि कॉरपोरेट घरानों को बेच दिए है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित चार लेबर कोड ट्रेड यूनियन आंदोलन को दबाने, काम के घंटे बढ़ाने और कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने के लिए बनाए गये हैं।

पुलिस ने 2 किलो 84 ग्राम चरस बरामद करने में मिली सफलता

दिव्या दिल्ली- ऊषा (जवाली)

जिला पुलिस नूरपुर द्वारा 9जुलाई 2025 को बतीस मील में नाकाबन्दी के दौरान इनोवा गाड़ी से दो युवकों विनय कुमार पुत्र सागर निवासी नूरपुर तथा किशोरी लाल पुत्र तीर्थ राम निवासी गांव सियोली बंजार के कब्जे से 2 किलो 84 ग्राम चरस बरामद करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने में सफल हुए है

बही प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से सख्ती से पूछताछ की तो अन्य दो आरोपियों विद्या देवी पत्नी चमन लाल व चमन लाल पुत्र खुशी राम निवासी सुतराहड़ नूरपुर का नाम सामने आया। पुलिस ने पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए दोनों को सुतराहड़ से गिरफ़्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने चरस आरोपियों से पूछताछ करने के उपरांत इसमें संलिप्त अन्य दो आरोपियों विद्या देवी पत्नी चमन लाल व चमन लाल पुत्र खुशी राम निवासी सुतराहड़ को सुतराहड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। तथा पूरी गहनता से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में सहकारिता विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन

दिव्या दिल्ली- हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में सहकारिता विषय पर एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह जानकारी देते हुए राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राजगढ़ के शाखा प्रबंधक अजय धरवाईक ने बताया कि इस मौका पर स्कूल में छात्रों के सहकारिता विषय व बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई । छात्रों को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक ने कहा कि पहली सहकारी समिति जिला ऊना में वर्ष 1892 में बनी । वर्ष 1904 में पहला सहकारी समिति अधिनियम भारत में बना। वर्ष 1948 तक अकेले हिमाचल प्रदेश में 663 सहकारी समितियां गठित थी जिनके सदस्यों की संख्या 18,375 थी। 1956 में पहला सहकारी सभाएं अधिनियम हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ। वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन होने पर इस अधिनियम को विस्तार दिया गया। वर्तमान में सभी सहकारी सभाएं, सहकारी बैंक व अन्य सहकारी संस्थाएं हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम 1968 के अंतर्गत ही कार्य कर रही है ।भारत सरकार ने सहकारिता को सशक्त व मजबूती से करने हेतु 6 जुलाई 2021 को अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397